कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

Qku : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887
lnL;rk : +91(11) 23005798

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद व सुशील कुमार मोदी ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर रिपोर्ट

विकास की जय..... 15

संप्रग शासन में घोटाला..... 6

लेख

क्या श्रीमती गांधी ने अधिकृत कश्मीर को मुक्त कराने की.....
ykyÑ".k vkMok.kh..... 19

यूपीए : घोटालों द्वारा, घोटालों की, घोटालों के लिए सरकार
vEck pj.k of'k"B..... 21

बिहार के चुनाव परिणाम, विकास आस्था के परिणाम
lR;iky--..... 24

साक्षात्कार

jeu flag..... 30

मोर्चा / प्रकोष्ठ

fdlku ekpkZ % बीज विधेयक-2004 सम्बन्धी संकल्प..... 12
Hkkt;ek % राष्ट्रीय प्रशिक्षण बैठक..... 13

राज्यों से

egkjk"Vª % विशाल किसान जनसभा..... 14
mUkj izn'k % भाजपा महापौर सम्मेलन..... 26
fnYyh % जनाक्रोश रैली..... 27
e/; izn'k % राष्ट्रीय राजमार्ग बचाओ आन्दोलन..... 29

संपादक के नाम पत्र...

कांग्रेस की संस्कृति है भ्रष्टाचार

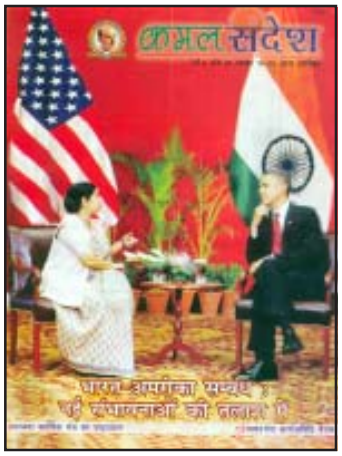

भले ही राष्ट्रमण्डल खेलों की पदक तालिका में भारत प्रथम स्थान पाने में असफल रहा हो किन्तु सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 'आटे में नमक खाने' की भ्रष्टाचार की सदियों पुरानी कहावत को पूरी तरह बदलते हुए 'नमक में आटा खाने' की भ्रष्टाचार की नई कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करते हुए महाघोटाले के विश्व रिकार्ड बनाने में पूरी तरह सफलता हासिल कर ली है। राष्ट्रमण्डल खेलों और आदर्श सोसायटी में हुए महाघोटालों पर जनता में हो रही भारी किरकरी से जनता का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकी संगठन सिद्ध करने का एजेंडा तैयार किया है। महाघोटालों पर पर्दा डालने की तमाम कोशिशें फेल होती देख आखिरकार सोनिया को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक राव चह्वाण को पद मुक्त और कलमाडी की संसदीय दल से छुट्टी करने का कदम उठाना ही पड़ा। भ्रष्टाचार और घोटालों में नित्य नए कीर्तिमान बनाने वाली कांग्रेस जनता को गुमराह करने में भी माहिर है। आज तक कांग्रेस के कितने नेता घोटालों में सजा पाए हैं यह सारा देश जानता है। सीबीआई का राजनैतिक इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस न्यायपालिका के काम में भी पूरा दखल रखती है।

कांग्रेस की दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया जबकि यमुना ज्यों कि त्यों मैली रही किन्तु शीला की साड़ी पर क्या घोटाले का मैल चढ़ा? दक्षिण राज्य में लो फ्लोर बसों की खरीद की कीमत से दुगुनी कीमतों पर दिल्ली में बसों की खरीद पर हुए घोटाले की क्या कोई जांच हुई? सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस घोटालों की सरताज है, भ्रष्टाचार उसकी संस्कृति है और सत्ता पाना उसका लक्ष्य है और इसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। उसके द्वारा कराई किसी भी जांच के न्यायिक परिणाम की आशा बेमानी होगी।

कमल कुमार जैन (कैलाश नगर, दिल्ली)

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

आपकी राय एवं विचार

सादर आमंत्रित

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

सम्पादकीय

बिहार चुनाव ने तय की राजनीति की नई दिशा

परिणाम आने के पूर्व परिणाम का आ जाना, इसे ही जन–अभिव्यक्ति कहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम तो 24 नवम्बर को आया पर परिणाम ऐसा ही आयेगा, इसकी चर्चा तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी। भाग्यशाली है जदयू–भाजपा गठबंधन। विकास पथ पर बिहार को ले जाने वाले जदयू–भाजपा गठबंधन को बिहार की जनता ने सत्ता पथ पर बनाए रखा और नीतीश कुमार और सुशील मोदी को जन–जन ने बहुमत के पुरस्कार से नवाजा। जनभावना को परिणाम में तब्दील करने की ताकत जनता में ही होती है। बिहार चुनाव की एक सबसे बड़ी खासियत रही कि किसी कोने से यह आवाज नहीं आ रही थी कि जदयू–भाजपा गठबंधन सरकार में नहीं आयेगी। हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात, विकास किया है इसलिए सरकार बनेगी। यह बात तो अब सिद्ध हो गई कि जो सत्ता विकास के प्रति वफादार नहीं होगा, वह सत्ता में टिक नहीं सकता।

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में राजग को तीन चौथाई से कहीं अधिक बहुमत मिला है। जदयू और भाजपा के गठबंधन एनडीए ने 206 सीटों पर जीत हासिल कर एक नए इतिहास की रचना की है। पिछले चुनाव के मुकाबले 36 अतिरिक्त सीटें जीतकर भाजपा सबसे अधिक फायदे में रही। लालू की पार्टी राजद को महज 22 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस की झोली में सिर्फ 4 सीटें आईं। परिणामों ने कांग्रेस, राजद, लोजपा को जरूर चौंकाया होगा पर जनता कतई नहीं चौंकी क्योंकि जनता को इसी तरह के परिणाम की आशा थी। बिहार की वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी बात जो उभरकर आयी, वह यह रही कि पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार की ध्वनि तक नहीं आई। जबकि लाखों–करोड़ों के विकास कार्य वहां हुये और हो रहे हैं। बिहार जात–पांत से उबरता नजर आ रहा है। बिहार का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ रहा है, यही कारण है कि नीतीश कुमार बिहार में विकास पुरूष के रूप में उभरे। उन्होंने गुंडागर्दी पर काबू पाया। बिहार की सड़कें स्वयं विकास की साक्षी बनीं। विद्यालयों की सुधरती व्यवस्था और उद्योग का आना बिहार के भविष्य की स्वयं कहानी लिख रहे हैं। 'बिहार प्रगति की ओर' जैसी ध्वनि को लोग स्वयं साकार होते देख रहे हैं। स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष सोनियाजी और उनके बेटे महामंत्री राहुल की पोल खुल गयी। वे कितने लोकप्रिय हैं, इसका अंदाज देशवासियों को लग गया। राहुल गाँधी ने जिन 22 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं, वहां केवल 2 स्थान पर कांग्रेस की जीत हुई। सोनिया जी और राहुल जी को जनता और कार्यकर्ता में अंतर समझना चाहिए। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं। मां–बेटे कांग्रेसी के लिए भगवान हो सकते हैं जनता के लिए नहीं। बिहार की जनता ने उस जदयू–भाजपा गठबंधन को स्वीकार किया, जिसने उनकी सेवा की, उनको नहीं जो बरसाती मेंढक की तरह चुनाव में टर्र–टर्र करने आ जाते हैं और चुनाव बाद गुम हो जाते हैं। स्थिति यही हो गई है कि सोनिया जी और राहुल जी राजनीतिक तौर पर बरसाती मेंढक बन चुके हैं। वे दोनों भूल जाते हैं कि जनता से उनका कोई सरोकार भी है। कांग्रेस बिहार में रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, दृष्टिविहीन और नेतृत्वविहीन हो चुकी है। महात्मा गांधी की कांग्रेस सोनिया गांधी तक आते–आते ऐसी हो जाएगी इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।

कांग्रेस इस समय भूल भुलैया में है। लालूजी इस चुनाव में हास्य–विनोद की वस्तु बन गए। पासवान 'आसमान से गिरे और खजूर पर अटके' वाली स्थिति में हैं। चाणक्य, चन्द्रगुप्त, भगवान महावीर और बुद्ध, मंडन मिश्र, विद्यापति, कालिदास, मां सीता, गुरूगोविन्द सिंहजी, जैसे प्रेरणास्पद व्यक्तियों की पावन माटी पर कुछ वर्षों में 'राजनैतिक कैक्टसों' के उग आने से बिहार की छवि धूमिल हो रही थी। लेकिन अब बिहार आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है और इस विधानसभा चुनाव परिणाम ने इस बात पर मुहर लगा दी कि बिहार विकास मार्ग पर चलता रहेगा। जातीयता, क्षेत्रीयता को नकारकर विकास को अपनाना, विधानसभा में जदयू–भाजपा को पुनः लाना उनके परिपक्व लोकतंत्र की समझ को ही दर्शाता है। ■

प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें : नितिन गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 18 नवम्बर, 2010 को प्रेस वार्ता में वक्तव्य जारी कर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से प्रश्न किया कि वे राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़े

ç- 1 प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बी. एस लाली के विरूद्ध अभी तक कोई आपराधिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जिन्होंने वित्त विभाग की आपत्तियों को अनदेखा किया और राष्ट्रीयमंडल खेलों के 246 करोड़ रूपये के प्रसारण अधिकार, एक ऐसी अवैध कम्पनी को दिये जिसने फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया और जिसके पास कोई सेवाकर नम्बर नहीं था ?

क्या श्री लाली को, जिन्होंने खेल समाप्त होने से पूर्व ही संविदा फीस की 80 प्रतिशत राशि का तुरन्त भुगतान कर दिया, उनके उच्च सम्बंधों के कारण –संरक्षण दिया जा रहा है? यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि संप्रग सरकार ने अभी तक आयकर विभाग के इन निष्कर्षों पर पूर्णतया चुप्पी साधी हुई है कि प्रसारण सौदा इंग्लैड की एक कम जानी पहचानी कम्पनी, एसआई एस लाइव (SIS Live) ने हासिल किया था।

जो बिड सम्बंधी औपचारिकताओं के पूरा होने के चार महीने बाद अस्तित्व में आई थी।

आयकर विभाग ने 6 अक्तूबर 2010 को एक पत्र भेजा था जिसमें भविष्य में किये जाने वाले सभी भुगतानों पर रोक लगाने के लिये कहा गया था और इसके साथ–साथ एकाटलैंडक के रायल बैंक की मुम्बई शाखा में कम्पनी के खाते को जब्त करने के लिए कहा गया था। जब आयकर अधिकारियों ने दिल्ली में एसआईएस लाइव के कार्यालय की छानबीन की तो उन्हें पता चला कि कम्पनी ने कोई खाता नहीं रखा और न ही कोई बिल रखे। आगे छानबीन से यह पता चला कि एसआईएस लाइव ने अनेक शर्तों का उल्लंघन किया। इसने एक अन्य कम्पनी, जूम कम्युनिकेशन (Zoom Communications) को उप–ठेके पर सौंप दिया, जो ओखला में उसी परिसर से अपना कार्यसंचालन करती हुई पाई गई। एसआईएस लाइव अधिकारी 177 करोड़ रूपये के उप–ठेके सम्बंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये थे।

अपनी टिप्पणी में आयकर रिपोर्ट में कहा गया है कि एसआईएस लाइव "राष्ट्रमंडल खेलों सम्बंधी ठेके को पूरा करने के एकमात्र उदेश्य से बनाई गई थी और कर–निर्धारिती के भारत में रहने की कोई संभावना नहीं है।"

ç- 2 श्री कनिष्क सिंह, जो श्री राहुल गांधी के निकट सहायक हैं, के ईएमएएआर एमजीफ के मलिकों के साथ क्या सम्बंध है जिसने घटिया राष्ट्रमंडल खेल फ्लैटों का निर्माण किया ?

किसके कहने पर दि.वि.प्रा. द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जोन के लिये 750 करोड़ रूपये एवं 827 करोड़ रूपये का वेलआउट पैकेज दिया गया ? क्या आप यह नही मानते कि उत्तरदायित्व पूरा न करने के लिए केवल ईएमएएआर एमजीफ बैंक गारंटी की शर्त रखना राहुल गांधी के साथी कनिष्क सिंह और उनके परिवार को बचाने के लिये मात्र दिखावा है।

ç- 3 क्या आप इस तथ्य से इंकार कर सकते है कि वर्ष 2009–10 Overlays के लिए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के योजना बजट में 126 करोड़ रूपये के प्रावधान में संशोधन करके उसे 687 करोड़ कर दिया गया जिसमें 557 करोड़ रूपये आयोजन समिति को

अग्रिम रूप से दिए गए। कृपया क्या आप कॉमनवेल्थ खेलों के Overlays के लिए किए गए प्रावधानों में इस प्रकार की भारी वृद्धि के औचित्य के बारे में देश को कुछ बता सकते हैं?

ç- 4 आपके खेल मंत्री ने राज्यसभा में यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं की लागत वृद्धि का कारण यह है कि प्रारंभिक अनुमान अधूरे, कम जानकारी के आधार पर स्वीकृत किए गये थे और राष्ट्रमंडल खेल संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के विभिन्न अनुमानों को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया था।

ç- 5 इस खेल कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति को 1669.42 करोड़ रू की अग्रिम राशि की स्वीकृति देने और OVERLAYS (अस्थायी फिटिंग एवं फिक्सचर इत्यादि) के लिए 687 करोड़ रू. की अग्रिम स्वीकृति देने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिसमें से 557 करोड़ रू. वास्तव में दिए गए और टाईमिंग, स्कोरिंग तथा रिजल्ट सिस्टम (TSR) और खेल टाईमिंग उपकरण के लिए अनुमोदित 37 करोड़ रू. में से वास्तव में 81 करोड़ रू. दिए गए?

अब जबकि खेलों से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय से हुई कुल आय कम है तो आप इस भारी अंतर को किस प्रकार पूरा करने जा रहे हैं? विज्ञापनों से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है और टिकटों की ब्रिकी से केवल 39.17 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है जबकि 375 करोड़ रू. की तयशुदा मूल्य की तुलना में 114.5 करोड़ रू. ही स्पांसरशिप के रूप में प्राप्त हुए और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अधिकारों के दिए जाने से 213.45 करोड़ रू. की तयशुदा मूल्य की तुलना में केवल 137.71 करोड़ रू. वसूल हुए।

ç- 6 कॉमनवेल्थ खेलों में लोगों की निराशाजनक उपस्थिति और टिकट ब्रिक्री में घपले के लिए आप किसे दोषी ठहराते है? क्या आपको इस तथ्य की जानकारी है कि साढ़े ग्यारह लाख छापी गई टिकटों में से केवल आधी टिकट ही दर्शकों द्वारा खरीदी गई?

मैं समझता हूं कि आपके खेल मंत्री ने आपको यह भी बताया होगा कि 3 अक्टूबर के उद्घाटन और 14 अक्टूबर के समापन के दौरान टिकटों की बिक्री में भारी घपला हुआ है, जिसके बारे में दर्शकों ने यह शिकायत की कि अनेक आसपास की सीटें खाली थी, जबकि अधिकारियों का दावा है कि सभी टिकटें बिक गई है।

उद्घाटन और समापन समारोह के लिए निःशुल्क टिकटों को भारी संख्या में छापने और एक ही सीट के लिए कई टिकटें छापने के लिए आप किसे बलि का बकरा बनाने जा रहे है?

ç- 7 आपकी सरकार ने यह दावा किया है कि राष्ट्रमंडल परियोजना से संबंधित ठेकेदारों, अधिकारियों और कुछ फर्मों के विरूद्ध उसने कार्यवाही शुरू की है। लेकिन, राष्ट्रमंडल खेल लूट में शामिल राजनैतिक व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कोई कार्रवाई की गई है? आपके खेल मंत्री के अनुसार, 22 मार्च 2007 से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री के समूह की 14 बैठकें हुई और पहले शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में 34 अतिरिक्त बैठकें हुई जिन्होंने 23 जून, 2009 से खेलों तक फिर से बनाए गए मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता की थी।

राष्ट्रमंडल खेलों की लूट में उनको मिले हिस्से की छानबीन कौन करेगा? राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में शामिल व्यक्तियों का पर्दाफाश केवल संयुक्त संसदीय समिति के गठन से ही हो पाएगा, जिसके लिए भाजपा संसद में और संसद के बाहर मांग करती आ रही है।

ç- 8 राष्ट्रमंडल खेल परियोजना के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा आबंटित 300 करोड़ रू. का क्या हुआ जो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया था। इस कार्य पर मुश्किल से कुछ करोड़ ही खर्च होते, जिसमें 7000 वर्ग फीट में निर्माण कार्य होना था और एक एकड़ क्षेत्र का सौंदर्यकरण होना था। यह धनराशि कहां गई ?

ç- 9 इसी प्रकार निम्नलिखित मामलों में की गई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में राष्ट्र को आपके प्रति उत्तर की प्रतीक्षा है।

क्वींसबैटन रिले, SMAM घोटाला ट्रेडमिल्स स्पांसरशिप, गेम वेबसाइट, टेनिस सरफेस, केटरिंग, मर्कैंडाइजिंग 22,000 स्वयंसेवकों की मान्यता 2,000 से अधिक स्टॉक और हजारों मीडियाकर्मी, खिलाड़ी और प्रतिनिधि, पार्किंग कनॉटप्लेस पुनर्विकास योजना, चांदनी चौक, पहाड़गंज, करोलबाग, शिवाजी, तालकटोरा स्टेडियम।

ç-10 विवादास्पद 2जी स्पैक्ट्रम निर्धारण मामले में श्री ए. राजा पर मुकद्दमा चलाने की स्वीकृति देने से आपके द्वारा निर्णय लेने में होने वाले विलंब संबंधी सीधे–सीधे प्रश्न के उत्तर देने से आपको कौन रोक रहा है। आप इस बारे में लोगों को क्यों नहीं बता रहे? ■

भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए अनावश्यक मुद्दों को तूल दे रही है कांग्रेस : राजनाथ सिंह

Hkk जपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने देशभर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार दिये जा रहे उग्र एवं हिंसक प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए कहा, कि जब राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक सुदर्शन जी के वक्तव्य से संघ ने न सिर्फ अपने को अलग कर लिया है, अपितु इस हेतु खेद भी व्यक्त कर दिया है, फिर भी देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा संघ कार्यालयों पर तोड़ फोड़ करते रहना औचित्यहीन एवं आलोचना के योग्य है।

श्री सिंह ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं या वक्तव्य हो जाते है जो किसी व्यक्ति या संगठन को आहत कर सकते है। परन्तु इस पर प्रतिक्रिया करने की मर्यादायें लोकतंत्र में परिभाषित है। स्पष्टीकरण एवं खेद के उपरान्त भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हिसंक प्रदर्शन कांग्रेस की संघ एवं अन्य हिन्दू संगठनों के प्रति वैमनस्य की मानसिकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ ने अपनी स्थापना के 85 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा से लेकर वनवासी कल्याण तक, मजदूर व किसानों के हित से लेकर मलिन बस्तियों में सेवा प्रकल्प तक जो कार्य किये हैं, वे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक भी ध्यानाकर्षण एवं शोध के विषय बने है, देश पर आक्रमणों, आपदाओं एवं कुछ सामाजिक संदर्भों में संघ की भूमिका की सराहना देश के प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद, पूर्व राष्ट्रपति डा0 राधाकृष्णन् एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री जी भी कर चुके हैं।

ऐसे समर्पित राष्ट्रभक्त संगठन को अभी कुछ दिन पूर्व ही कांग्रेस ने आतंकवादी संगठन सिमी के समकक्ष रखने का प्रयास किया। इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा तो संघ की तुलना लश्करे तैयबा जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों से भी करने का कुत्सित प्रयास किया गया। संघ के कतिपय शीर्षस्त पदाधिकारियों को आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास भी किया गया। foxr dbl eghuk l dkxl d ofj"B urkvk d }kjk doy dN dVVjiFkh 'kfDr;k dk lr"V dju d fy, *Hkxok vkrdokn* tl 'kCn dk i;kx fd;k x;kA fdlh Hkh ij d ij lekt] lEink; ;k èkel dk vkrdokn l tkMu dk dkxl dk ;g vijkèk cgr xEHkhj gA l?k vkj Hkktik u bldk fojkèk 'kkfUr i.k èkjuk in'kku d ekè;e l ntl fd;kA dkxl ;k ljdkjh dk;ky;k ij rkM QkM djd ughA

अपने प्रतिकूल निर्णय, घटना अथवा टिप्पणी पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया परम्परा से ही अधिनायकवादी रही है। चाहे 1975 में न्यायालय से विपरीत निर्णय आने पर इन्दिरा जी के नेतृत्व की कांग्रेस की प्रतिक्रिया रही हो, चाहे 1984 में इन्दिरा जी की दुःखद हत्या के बाद भड़के सिक्ख विरोधी दंगों में राजीव जी के नेतृत्व की कांग्रेस की प्रतिक्रिया रही हो अथवा आज कांग्रेस की इस विषय पर प्रतिक्रिया हो। यह निरन्तर सत्ता से निकली हुई उस सामन्तवादी मानसिकता का प्रकटीकरण है, जो अपने प्रतिकूल किसी भी चीज को नष्ट कर देना चाहती है।

पूर्व में संघ एवं भाजपा के अनेक नेताओं जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी भी शामिल हैं, उन पर भी अनेक बार आपत्तिजनक टिप्पणियां की गयी। परन्तु इन पर हमारी प्रतिक्रिया सामाजिक एवं लोकतांत्रिक मर्यादा की सीमा में रही। यदि आज कांग्रेस को लगता हैं कि संघ के स्पष्टीकरण एवं खेद व्यक्त करने के बाद भी वे असंतुष्ट हैं, तो उनके लिए सामाजिक, राजनैतिक और वैधानिक सभी विकल्प खुले हैं। वे अपनी संतुष्टि के लिए कोई भी विकल्प चुन सकते है। परन्तु उग्रता और हिंसा का विकल्प लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

कांग्रेस की इन हरकतों से देश की जनता के मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि पिछले कुछ महीनों में आईपीएल से लेकर भोपाल गैस प्रकरण, खाद्यान्न घोटाले से लेकर 2–जी स्पेक्ट्रम और आदर्श सोसायटी घोटाले तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबती जा रही कांग्रेस इन गम्भीर मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए अनावश्यक एक ऐसे मुद्दे को तूल देकर रखना चाहती हैं जो स्पष्टीकरण के साथ समाप्त हो चुका है।■

प्रधानमंत्री की नाक के नीचे घोटाले दर घोटाले : रविशंकर प्रसाद

प्रश्न, जिनका उत्तर प्रधानमंत्री जी द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के संदर्भ में दिया जाना अनिवार्य है

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा 20 नवम्बर, 2010 को जारी वक्तव्य

ok स्तव में ये बड़े अचंभे और आश्चर्य की बात है कि कल से मंत्री और कांग्रेस के नेता अचानक 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधी भारी घोटाले के बारे में प्रधानमंत्री के बचाव में आ गये हैं। इस घोटाले से राष्ट्र को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए की भारी हानि हुई है। फिर भी, इस अचानक 'राग दरबारी' से यह अटल सत्य छुपाया नहीं जा सकता। यह एक ऐसा स्पष्ट मामला है, जिसमें प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का 'चुप्पी साधने का षड्यंत्र', 'उदासीनता का अपराध' और 'अकर्मण्यता की पराकाष्ठा' होना स्पष्ट प्रतीत होता है, जबकि व्यवस्था का भारी दुरुपयोग करके उनकी नाक के नीचे एक मंत्री द्वारा राष्ट्र की संपत्ति को लूटा जा रहा था और फिर भी सरकार के मुखिया डा. मनमोहन सिंह कहीं और ही देखते रहे। प्रधानमंत्री की निष्ठा के बारे में प्रशंसा किये जाने से उनकी निष्क्रियता और लापरवाही के धब्बे को नहीं धोया जा सकता। राष्ट्र को अपना स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार है।

भाजपा चाहेगी कि प्रधानमंत्री जी परेशान करने वाले उन प्रश्नों का उत्तर दें जो राष्ट्र के लिए दो वर्ष से अधिक समय तक परेशानी का कारण बने रहे।

1. जब खुली लाइसेंस प्रणाली की सिफारिश की गई थी और 1 अगस्त, 2007 तक आवेदन मांगे गये थे, तब बाद में, 25.9.2007 को, कृत्रिम अंतिम तारीख निर्धारित की गई और 25,9.2007 और 1.10. 2007 के बीच प्राप्त आवेदनों को देखते ही क्यों रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी! आप उस समय क्यों खामोश रहें जब ये सब प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रक्रिया संबंधी नियमों में परिवर्तन किए गए और इसके बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी बहुत ही प्रतिकूल टिप्पणी की थी।
2. किसी भी लाइसेंस को तब तक परिचालित नहीं किया जा सकता जब तक किसी व्यक्ति को स्पेक्ट्रम, जो एक दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन है, नहीं मिल जाता। आपने इसे वर्ष 2007 में 2001 के विद्यमान मूल्य पर बेचने की अनुमति क्यों दी जबकि देश में टेली–घनत्व बढ़कर 7 गुना हो गया था। इस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना ही होगा क्योंकि 2 नवंबर, 2007 को प्रधानमंत्री जी ने श्री राजा को स्पेक्ट्रम के सही मूल्य के लिए नीलामी की पारदर्शी प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए एक पत्र लिखा था। फिर भी प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी, 2008 के अपने पत्र के द्वारा दूसरा दृष्टिकोण अपनाया जिसके अनुसार तत्कालीन संचार मंत्री श्री राजा 'ऑपरेशन लूट' को चालू रख सकते हैं।
3. प्रधानमंत्री ने समूची फाइल को अपने पास क्यों नहीं मंगाया और अपनी प्रतिकूल टिप्पणी क्यों नहीं दी जबकि सभी मापदंडों का खुले तौर पर भारी उल्लंघन किया जा रहा था?
4. प्रधानमंत्री ने 2जी स्पेक्ट्रम के समूचे आवंटन की पुनरीक्षा करने और जांच करने के आदेश क्यों नहीं दिए जबकि 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को 35 हजार करोड़ रुपए लक्ष्य की तुलना में 1 लाख करोड़ का भारी लाभ हुआ।

5. प्रधानमंत्री उस समय क्यों मौन रहे जब 85 अयोग्य कंपनियों (कैग रिपोर्ट के अनुसार) को आशय–पत्र दिये गये और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जिन कंपनियों को लाइसेंस मिले उन्हें स्पेक्ट्रम के व्यापार करने की अनुमति भी दी गई। इसके परिणामस्वरूप 'स्वान टेलीकॉम', जिसे 15 सौ करोड़ रुपए का लाइसेंस मिला और यूनिटेक, जिसे लगभग 16 सौ करोड़ का लाइसेंस मिला और अन्य अनेक कंपनियों ने अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा अपने विदेशी सहभागियों, जो रातों–रात अस्तित्व में आ गईं, को 7000–9000 करोड़ रुपए के मूल्य पर बेच दिया। जब ऐसा सब कुछ हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे रहे जबकि 2जी स्पेक्ट्रम को जान–बूझकर कम मूल्य पर बेचने के कुछ प्रमाण सामने आ गये थे।
6. इस समूचे मामले पर संसद में जुलाई 2009 में विस्तृत चर्चा की गई थी और इस संबंध में एक अस्पष्ट उत्तर दिया गया जबकि उपर्युक्त सभी तथ्य और आज कैग द्वारा कही गई अधिकांश बातें भाजपा द्वारा ध्यान में लाई गई थीं।
7. सीबीआई ने अक्टूबर 2009 में मामले की छानबीन आरंभ कर दी थी और अंतिम रिपोर्ट में यह पाया कि लगभग 25 हजार करोड़ का घोटाला हुआ। दूरसंचार मंत्रालय में पड़े छापे के बावजूद सीबीआई को दूरसंचार सचिव और अन्य प्रमुख अधिकारियों से पूछताछ करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? ए राजा से पूछताछ करने की अनुमति देना अथवा उसके विभाग को बदलने (उन्हें हटाने से बहुत नीचे की बात) की बात तो दूर रही, प्रधानमंत्री ने दूरसंचार सचिव को जबरदस्ती सीवीसी नियुक्त करके निष्ठा के स्तर को बहुत नीचा कर दिया है।

ये कुछ परेशान करने वाले प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रधानमंत्री जी ने जान–बूझकर और सोच–समझकर नहीं दिया। भारत में एक चिंताजनक एवं दुखदायी स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि वे एक महान निष्ठा वाले व्यक्ति हैं और ईमानदारी की पैरवी करते हैं, फिर भी उनकी नाक के नीचे लाखों करोड़ों रुपए की धनराशि ऐसे लोगों द्वारा बड़े व्यवस्थित ढंग से लूटी जा रही है जो सरकार का एक हिस्सा हैं और उनके अधीन कार्य करते हैं।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का 'चुप्पी साधने का षड्यंत्र', 'उदासीनता का अपराध' और 'अकर्मण्यता की पराकाष्ठा' होना स्पष्ट प्रतीत होता है, जबकि व्यवस्था का भारी दुरुपयोग करके उनकी नाक के नीचे एक मंत्री द्वारा राष्ट्र की संपत्ति को लूटा जा रहा था और फिर भी सरकार के मुखिया डा. मनमोहन सिंह कहीं और ही देखते रहे।

यह 2जी स्पेक्ट्रम का घोटाला हो या राष्ट्रमंडल खेल आयोजन का घोटाला या कोई और घोटाला। राष्ट्र इस बेसुरा राग दरबारी पर विश्वास नहीं करेगा और जनता अपना निष्कर्ष खुद निकालेगी।

प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी दलों से संसद चलने दिए जाने और चर्चा करने के लिए अपील की है। भाजपा प्रधानमंत्री जी को बताना चाहेगी कि हमने बार–बार चर्चा और वाद–विवाद किए और प्रश्न पूछे। प्रधानमंत्री जी आपने शुरू में श्री राजा का बचाव किया और सच तो यह है कि संसदीय दबाव के कारण ही आपने उन्हें त्याग–पत्र देने को कहा। प्रधानमंत्री जी आप चर्चा चाहते हैं लेकिन भाजपा कार्रवाई चाहती है और चाहती है कि उत्तरदायी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाए।

हम चाहते हैं श्री ए राजा और लाभ पाने वाले व्यक्तियों सहित उनके सहयोगियों से पूछताछ की जाए। उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया जाए। केवल संयुक्त संसदीय समिति ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ऐसा सब कुछ करना सुनिश्चित हो सकता है। यह बात याद करने योग्य है कि सभी विपक्षी दलों की एक बैठक श्री प्रणव मुखर्जी के साथ संसद में हुई जिसमें सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर से संयुक्त संसदीय समिति की मांग की थी और जिसमें दोनों सदनों में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी उपस्थित थे।

श्री मुखर्जी ने बैठक में आश्वासन दिया था कि वह प्रधानमंत्री से सलाह–मशविरा करने के बाद आपके साथ पुनः बैठक करेंगे। आज तक उन्होंने कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा जिससे विपक्षी दल अपना अंतिम दृष्टिकोण तय कर सकें। ■

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने यूपीए की कलई खोली : प्रकाश जावडेकर

rh न चौंकाने वाले रहस्य जो आज ही जनता के सामने आये हैं, से 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में संप्रग सरकार की संलिप्तता और उसे दबाने के उनके इरादों का पूरी तरह पर्दाफाश हो गया है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल, श्री गोपाल सुब्रहमण्यम की उपस्थिति में जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों और राजा के वकील की विधि अधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक घोटाले को दबाने का स्पष्ट प्रमाण है और ऐसा करना माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है। जब उच्चतम न्यायालय की पीठ के समक्ष सोमवार को मामले की सुनवाई तय है तो विधि अधिकारी उच्च अधिकारियों के निर्देश के बिना इस प्रकार की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित नहीं कर सकते। हमारी जानकारी के अनुसार अन्य अधिकारियों के अलावा सॉलिसिटर जनरल, राजा के वकील, अनीता शिनॉय, डीआईजी (एसीबी) श्री पलसानिया और जांच कर रहे सीबीआई संबंधित अधिकारी श्री विवेक प्रियदर्शी को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में यह निर्णय लिया जाना था कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष किस प्रकार की एकीकृत रणनीति अपनाई जाये। इस प्रकार की बैठक और ऐसे प्रयास के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। यह पूर्णतया अनैतिक है तथा मामले को सरकार द्वारा दबाने का स्पष्ट प्रमाण है। बावजूद इसके बैठक की बात लीक होने पर

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा 13 नवम्बर, 2010 को जारी प्रेस वक्तव्य

संयोजक अधिकारी का तबादला कर दिया गया है।

निर्धारित समयावधि में कार्य आरम्भ न करने के लिए लाइसेंसों को अब तक रद्द कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा करने से श्री राजा के प्रयासों की सरकारी संरक्षण मिलना साबित होता है।

दूर–संचार विभाग के पूर्व सचिव, श्री डी.एस. माथुर का साक्षात्कार इस बात का ठोस प्रमाण है कि 2जी स्पैक्ट्रम प्राकृतिक न्याय अथवा समान और पारदर्शी नीति के किसी भी सिद्धांत का पालन न करते हुए अलॉट किया गया था। श्री राजा का एजेंडा पहले दिन से पूरी तरह स्पष्ट था। वह अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किए बिना और इस बात की परवाह किए बिना कि क्या स्पैक्ट्रम उपलब्ध है या नहीं, 500 नये लाइसेंस जारी करना चाहते थे। यद्यपि वह स्पैक्ट्रम की सार्वजनिक नीलामी का हमेशा विरोध करते रहे, तथापि अब यह बात स्पष्ट हो गयी है कि यह एक प्रकार की "निजी निलामी" थी। चौंकाने वाली बात यह है कि राजा किस प्रकार लाइसेंसों के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने की "कट–ऑफ" तारीख बढ़ाते रहे और किस प्रकार कुछ ईमानदार अधिकारी इस निर्णय से सहमत नहीं हुए और कुछ तो समय से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये। ये बातें आँखें खोलने वाली है। यहां तक कि सक्षम आवेदकों के बारे में निर्णय लेने हेतु कोई नीति न बनाना भी इस बात का प्रमाण है कि अलाटमेंट एक पूर्व निर्धारित षड्यंत्र था।

निर्धारित समयावधि में कार्य आरम्भ न करने के लिए लाइसेंसों को अब तक रद्द कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा करने से श्री राजा के प्रयासों की सरकारी संरक्षण मिलना साबित होता है। अब टीआरएआई मामले को देखेगी।

प्रधानमंत्री एक मूकदर्शक बने नहीं रह सकते और इस मामले में वह अब तक जो कर रहे थे अब उससे हट कर कार्यवाही करें।

भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी और महासचिव श्री राहुल गांधी से अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की भी मांग करती है वे दुविधा पैदा करने वाले मुद्दों पर न बोलना पसन्द कर सकते है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति लोगों को सदैव बेवकूफ नहीं बना सकता।■

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा पारित प्रस्ताव

बीज विधेयक – 2004 सम्बन्धी संकल्प

यूपीए सरकार के शासनकाल में उनकी किसान–विराधी नीतियों के कारण किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाएँ बढ़ती जा रही है। आत्महत्याओं के पीछे एक कारण किसानों को नकली बीजों की सप्लाई है। यूपीए सरकार नकली बीजों की सप्लाई को रोकने तथा बीजों की कीमतों को विनियमित करने में असफल रही है। शासकों तथा अधिकारीगणों ने इस सम्बन्ध में अपनी असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि बीज अधिनियम 1966 इतना सख्त नहीं है जिसके अन्तर्गत नकली बीजों की सप्लाई रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सके। इसी उद्देश्य से सरकार ने बीज विधेयक 2004 के रूप में एक नया अधिनियम बनाने का प्रस्ताव रखा है। दुर्भाग्यवश बीज विधेयक 2004 सरकार के पास वर्ष 2004 से विभिन्न स्तरों पर लम्बित पड़ा है जिनका कारण केवल सत्तारूढ़ दल ही जानते हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इसके लिए केन्द्र सरकार को दोषी मानती है क्योंकि बीज उत्पादों के साथ उसकी मिलीभगत है जिसके परिणामस्वरूप विधेयक लम्बित है और आज तक संसद में पेश नहीं किया गया है।

प्रस्तावित बीज विधेयक 2004 इतना व्यापक नहीं है कि इससे नकली बीजों की सप्लाई रोकी जा सके। बीज अधिनियम 1966 और प्रस्तावित बीज विधेयक 2004 में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। बीज मूल्यों की विनियमित करने तथा किसानों को दिए जाने वाले मुआवज़े की मात्रा के बारे में कहीं भी कोई उल्लेख इसमें नहीं है। प्रस्तावित बीज विधेयक 2004 किसानों की बजाए बीज उत्पादों तथा वितरकों के लिए ज्यादा लाभपद्र सिद्ध होगा। इससे नकली बीजों की बिक्री में कोई कमी नहीं होगा क्योंकि बीज समितियों का गठन और दूसरे देशों में बीज प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया तथा बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की मान्यता प्रदान करना बीज उत्पादकों के पक्ष में है।

बीज उत्पादक भ्रष्ट तरीकों से अपने बीज प्रमाणीकरण को मान्यता प्रदान करवाते हैं जिससे किसानों को नुकसान होता है। प्रस्तावित विधेयक में गुणवत्ता के आधार पर बीज प्रमाणीकरण को मान्यता प्रदान किए जाने की आशा नहीं कर सकते इसके अलावा प्रस्तावित कानून से नकली बीज उत्पादकों तथा वितरकों को ही लाभ मिलेगा।

बीजों के मूल्यों को विनियमित करने सम्बन्धी जीएम तकनालॉजी सहित, सभी उपबन्धों को शामिल किए जाए।

प्रस्तावित विधयक के पीछे यूपीए सरकार का आशय बीज प्रक्रिया तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भरता और अधिक ही है क्योंकि इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा बीजों के उत्पादन में वृद्धि किए जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं यह सरकारी दायित्व है कि वे निजी एजेंसियों पर निर्भर करने के बजाए उत्तम किस्म के एवं अधिक उत्पादन देने वाले बीज ख़रीदे तथा किसानों को सप्लाई करें प्रस्तावित विधेयक में सरकार ने बीजों के मूल्यों को विनियमित करने सम्बन्धी कोई उपबन्ध शामिल नहीं किया है और किसानों को बीज उत्पादकों की दया पर छोड़ दिया है। यूपीए सरकार ने भी उत्पादकों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में मूल्यों को विनियमित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए है। इसी कारण उसमें इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान नहीं किए है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आवश्यक उपबन्ध शामिल किए जाने की मांग करता है जिससे सरकार बीजों के मूल्यों को विनियमित कर सके।

विधेयक में किन्हीं विशष परिस्थितियों में बीजों से आशानुकूल उत्पादन न मिलने पर किसानों को दिए जाने वालो मुआवजे की मात्रा तय करने के तरीकों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। हमारा सुझाव है कि ऐसे हालात में मुआवजे की मात्रा तय की जाए और इस धनराशि का भुगतान किसानों को एक निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

यूपीए सरकार की सहानुभूति उन लोगों के साथ अधिक है जो बीज विधेयक 2004 के उपबन्धों का उल्लघंन करेंगे। विधेयक में निर्धारित सजा बहुत ही कम हैं अतः हम मांग करते हैं कि बीज उत्पादकों तथा नकली बीजों के सप्लाईकर्ताओं को ऐसा करने से राके ने के लिए सजा को बढ़ाकर अधिकतम स्तर तक किया जाय। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मांग करता है कि यूपीए सरकार को बीज विधेयक इस आशय से लाना चाहिए जिसमें किसान बीज उत्पादकों के पंजों से मुक्त हो सके तथा उन्हें लाभ मिल सके। हम यह भी मांग करते हैं कि विधेयक को आगामी संसद सत्र में पेश किया जाय और इसमें निम्नलिखित सुझाव शामिल किए जाएँ।

1. बीजों के मूल्यों को विनियमित करने सम्बन्धी जीएम तकनालॉजी सहित, सभी उपबन्धों को शामिल किए जाए ।
2. यदि उत्पादकों द्वारा बताए अनुसार बीजों से आशानुकूल उत्पादन नहीं मिलता तो उस हालात में मुआवजे की मात्रा पूरे फसल के दाम के बराबर निर्धारित की जाय।
3. मुआवजे का दायित्व बीज बेचने वाली कम्पनी पर डाला जाय, अथवा बीमा कम्पनियों पर जिसका प्रीमियम बीज बेचने वाली कम्पनी अदा करे।
4. नकली बीजों का उत्पादन करने तथा उनकी सप्लाई करने के लिए निर्धारित दण्ड को बढ़ाया जाय तथा गलत काम करने वालों के लिए कैद की सजा और कठोर होनी चाहिए।
5. विदेशी बीजों के प्रमाणीकरण की अनुमति भारत में उचित परीक्षण किए जाने पर ही दी जानी चाहिए।
6. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा सरकारी एजेंसियों द्वारा उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन उढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
7. बीज प्रमाणीकरण को मान्यता बीजों की गुणवत्ता की जांच किए जाने के बाद ही प्रदान की जानी चाहिए।
8. विवादों के निपटारे के लिए केन्द्र और राज्य एवं जिला स्तरों पर समितियों का गठन किया जाय जिनमें किसानों की अध्यक्ष और सदस्य के रूप में 50 प्रतिशत भागीदारी हो।
9. विकसित बीज को 10 वर्ष तक का लाइसैन्स दिया जाय। बाद में उसका नवीनीकरण न किया जाय ताकि बीज का सार्वजनिक उपयोग बिना रायल्टी के हो सके। ■

भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय प्रशिक्षण बैठक संपन्न

गत 12 नवम्बर, 2010 को भाजपा केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रशिक्षण संबंधी पहली राष्ट्रीय बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्घाटन भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डा. महेश चन्द्र शर्मा ने करते हुए राजनैतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान राजनैतिक और वैचारिक चुनौतियों का सामना करने के लिए सुविचारित प्रशिक्षण कार्यकर्ता की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सह–प्रभारी श्री राम प्यारे पांडे ने द्वितीय सत्र को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण वर्ग को प्रभावी बनाने हेतु प्रमुख बिन्दुओं की चर्चा की। तीसरे सत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री आलोक कुमार ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाये गये केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया है। प्रथम स्तर को प्रवेश, द्वितीय स्तर को प्रगत व तृतीय स्तर को प्रवीण कहा गया है। प्रशिक्षण बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवा मोर्चा प्रशिक्षण हेतु बनाई गई पार्टी की योजना के अनुरूप मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेगा। उन्होंने कहा कि सारे देश में प्रदेश कार्यसमिति स्तर के सभी कार्यकर्ताओं का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण 31 दिसम्बर, 2010 तक व जिला स्तर के प्रशिक्षण फरवरी 2011 तक संपन्न होंगे।

बैठक का संचालन राष्ट्रीय महामंत्री मनोरंजन मिश्र ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सर्वश्री पुष्यमित्र भार्गव, राजेश यादव, कु. वन्दना भगत, राकेश शर्मा, मनोज पाठक, कु. हर्षिका वर्मा, हितेश शुक्ला तथा पंजाब युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री गुरू परवेज सिंह 'शैले', युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री सर्वश्री राघवेन्द्र, सिद्धेश नायक, समय सिह भाटी, यशवीर राघव, सत्यवान शेरा, सुनील ठाकुर, हितेश पटेल, मनजीत, कृष्ण दीक्षित 'बड़े', राम कुमार, दीपक, अमित, हर्ष, कमल गर्ग शामिल थे। ■

भाजपा गरीब किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए कृतसंकल्प : नितिन गडकरी

गत 21 नवम्बर को जामनी जिला, वर्धा, महाराष्ट्र में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने किसानों की एक विशाल जनसभा को सम्बोधित किया।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने विदर्भ क्षेत्र में किसानों की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उनकी खुशहाली के लिए काम करें ताकि उनकी आत्महत्याओं को रोका जा सके।

वर्धा जिले से सेलू तहसील में जामनी गांव में एक विद्युत उत्पादन परियोजना का शिलान्यास करते हुए एक विशाल जनसमूह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज यह स्थिति है कि ''किसान की टोपी भूमि विकास बैंक के पास, कुर्ता सहकारी बैंक के पास और धोती साहूकार के पास गिरवी पड़ी रहती है।''

उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब और अति–गरीब किसानों को साहूकारों के शिकंजे से बचाने का हर सम्भव प्रयास करेगी और उनके कल्याण के लिए कार्य करेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने देश के कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी पार्टी की वचनबद्धता दोहराई। और उन्होंने कहा कि हमारा यह ग्रुप किसानों और आम आदमी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि पूर्ति ग्रुप 15 लाख रूपए का नुकसान होने बावजूद जामनी स्थित एक फैक्टरी सहित सभी तीन चीनी मिलों में अपना कामकाज चलाता रहा है ताकि किसानों को लाभ मिले।

उन्होंने कहा कि चीनी उत्पादन के दौरान इथनॉल प्राप्ति से पूर्ति ग्रुप 17 करोड़ रूपए का बिजली उत्पादन कर रहा है जिसे मुम्बई को दिया जाता है। इससे पूर्ति ग्रुप अपनी चीनी मिलों के कामकाज से होने वाले नुकसान की भरपाई कर पाता है।

उन्होंने कहा कि पूर्ति ग्रुप उद्योगों

में लगभग 13000 किसानों ने 90 करोड़ रूपए का अंशदान किया है जबकि उनका अपना अंशदान मात्र एक लाख रूपए है।

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि किसानों को को खुद अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए और उनसे अपील की कि उन्हें सरकारी समर्थन पर निर्भर न रहकर अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से काम करना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने पूर्ति ग्रुप द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी सामाजिक योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रुप ने गरीब किसानों के बच्चों के लिए 1.50 करोड़ रूपए की छात्रवृत्तियां मंजूर की है। पूर्ति ग्रुप ने समग्र रूप से हृदय रोग से पीड़ित 1400 लोगों का निःशुल्क इलाज कराया है। पूर्ति ग्रुप कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ को गरीब किसानों की शिक्षा और स्वास्थ्य तथा कृषि विकास पर खर्च किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली कटौती की समस्या से बचने के लिए सौर उर्जा से संचालित बोर–बैलों की स्थाना की जाएगी।

इस अवसर पर दत्त मेघे, सांसद (वर्धा), सुधीर मंघंटी वद, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, देवेन्द्र फड़नवीस, विधायक तथा भाजपा महासचिव, अशोक शिंडे, हिंगनघाट विधायक, वरिष्ठ भाजपा नेता अरूण अदसाद, सुरेश देशमुख, वर्धा विधायक, दादाराव केचे, अरवी, विधायक, सुधाकर राव देशमुख, पश्चिम नागपुर विधायक, कृष्णा खोपड़े, पूर्वी नागपुर विधायक, चन्द्रशेखर बावंकुले, काम्पटी, विधायक और नागपुर जिला प्रमुख भाजपा, तथा अन्य विशिष्टगण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

सुधीर दवे, सीईओ और प्रबंध निदेशक, पूर्ति ग्रुप उद्योग ने उद्घाटन भाषण दिया तो विजयराव मुड़े वाइस–चेयरमैन, महात्मा शूगर एंड पावर लि. ने आभार प्रगट किया। ■

विकास को वोट जातिवाद-परिवारवाद पर चोट

l;tho dekj flUgk

बिहार के 15वें विधानसभा के चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल(यूनाइटेड) शामिल है, ने अभूतपूर्व जीत हासिल कर नया इतिहास रच दिया। भारत के विधानसभा चुनावों के इतिहास में राजग गठबंधन की यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं लालू–पासवान को भारी झटका लगा और कांग्रेस की हालत खराब हुई। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में राजग को तीन चौथाई बहुमत मिला। उसके 206 उम्मीदवार जीत गये। जदयू ने सर्वाधिक 115 सीटें हासिल की जबकि भाजपा ने 91 सीटों पर जीत दर्ज की। राजग गठबंधन के तहत जदयू ने कुल 243 सीटों में से इस बार 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था जबकि भाजपा ने 102 सीटों पर। विपक्ष को करारी शिकस्त देते हुए राजग ने साल 2005 के चुनाव की तुलना में अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। साल 2005 में गठबंधन को 143 सीटें प्राप्त हुई थी। इस चुनाव में लालू प्रसाद और रामविलास पासवान की पार्टी ने गठजोड़ कर चुनाव लड़ा था। राजद–लोजपा गठबंधन को कुल 25 सीटें प्राप्त हुई जिसमें से राजद को 22 सीट तथा लोजपा को तीन सीटें मिली। कांग्रेस को भी करारा झटका लगा और उसे केवल चार सीटें ही मिली हैं जबकि पिछली बार उसे नौ सीटें मिली थीं। वाम दलों ने इस बार तालमेल कर चुनाव लड़ा था लेकिन वह भी काम नहीं आया और केवल एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी को मिली। निर्दलीय व अन्य उम्मीदवारों ने कुल आठ सीटों पर जीत दर्ज की। अपनी ऐतिहासिक जीत से उत्साहित भाजपा और जदयू कार्यकर्ता जश्न मनाने बिहार के चप्पे–चप्पे सहित देश के अनेक राज्यों में सड़कों पर उतर पड़े। पटाखे चलाकर दिवाली मनाई। ढोल की थाप पर खूब थिरके। मिठाई भी बांटी गई। कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लहराते हुए जमकर नारे लगाए।

जातिवाद को ध्वस्त किया

राजग उम्मीदवारों को सभी वर्गों का अपार जनसमर्थन मिला। मतदाताओं ने जातिवाद के महारोग को ध्वस्त करते हुए जात–पांत से ऊपर उठकर विकास को लेकर मतदान किया। इस बार राजग के विकास के एजेंडे के सामने लालू का 'माई(मुसलमान–यादव)' समीकरण ध्वस्त हो गया। जातीय समीकरण नहीं, विकास का जादू चला।

ऐतिहासिक जीतः '७७ की लहर पर भारी पड़ा 'राजग लहर'

बिहार विधानसभा चुनाव में राजग के पक्ष में चली लहर ने वर्ष 1977 के चर्चित चुनाव में जनता पार्टी को मिली सीटों के प्रतिशत को भी पीछे छोड़ दिया। विदित हो कि 243 सदस्यीय

विकास और सु
एजेंडे की जीत : नि

बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों को वि
जीत बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र
कहा कि भाजपा के हिन्दुत्व का म
ही है। राज्य की गठबंधन सरक
हुए गडकरी ने उम्मीद जताई
चार–पांच राज्यों में शामिल होगा।
श्री गडकरी ने कहा, यह जन
रूझान था, जिसने इतने भारी बहु
गडकरी ने मुताबिक, पहले राजद अ
के 15 वर्षों के कुशासन के बा
अहसास हुआ कि सरकार बदलद
राजग सरकार की सबसे बड़ी उप
यह भरोसा पैदा किया। पहली
को सजा मिली। स्कूलों में टीच
रहने लगे। सड़कें ठीक
इस
नहीं

वाले सदन में राजग ने 206 सीटें जीतीं हैं। इस तरह यह लगभग 82 फीसदी सीटें हो जाती है। जबकि आपातकाल के बाद वर्ष 1977 में हुए ऐतिहासिक चुनाव में जनता पार्टी 214 सीटें जीतकर बिहार विधानसभा के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। लेकिन अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए तो जनता पार्टी को कांग्रेस के विरोध में चली लहर के बावजूद 324 (बिहार एवं झारखंड) सदस्यीय सदन में 70 फीसदी सीटें ही मिल पाई थीं।

एंटी इनकैंबेसी फैक्टर बेअसर

आमतौर पर विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी के विरूद्ध एंटी इनकैंबेसी फैक्टर का लाभ मिलता रहा है। लेकिन बिहार में हवा का रूख सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहा। एनडीए गठबंधन को मिली 206 सीटें इस बात को साबित कर रही है।

जदयू बनी सबसे बड़ी पार्टी

वर्ष 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल (यूनाइटेड) ने जहां 88 सीटें जीती थीं, वहीं इस बार भी वह सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसे 115 सीटों पर जीत हासिल हुई।

सबसे अधिक फायदे में भाजपा

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। 2005 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा सबसे ज्यादा फायदे

सफलता का 'स्ट्राइक रेट'

2005 के नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव और ताजा चुनाव में हासिल वोटों की तुलना करें तो कांग्रेस के वोट में एक प्रतिशत इजाफा तो हुआ, पर उसे पांच सीटें गंवानी पड़ीं। राजग के वोट में तीन फीसदी की वृद्धि ने 63 सीटों का इजाफा कर दिया। राजद–लोजपा के वोट प्रतिशत में 10 फीसदी की कमी आई और सीटों की संख्या 64 से गिरकर 25 पर पहुंच गई। भाजपा को मिलने वाली सफलता अप्रत्याशित है। कुल खड़े 102 उम्मीदवारों में 91 जीते। यानी स्ट्राइक रेट (सफलता की दर) 89.21 प्रतिशत। जदयू का स्ट्राइक रेट 80.14 प्रतिशत रहा। उसके 141 में से 115 उम्मीदवार विधानसभा में पहुंचे। कांग्रेस की स्थिति खराब ही कही जाएगी। राहुल–सोनिया के तमाम दौरों और केंद्रीय मंत्रियों के दर्जनों कार्यक्रमों के बावजूद स्ट्राइक रेट सिर्फ 1.6 प्रतिशत रहा। पार्टी के 243 उम्मीदवारों में सिर्फ चार प्रत्याशी ही जीते। राजद का स्ट्राइक रेट 13 तो लोजपा का चार प्रतिशत रहा।

और सुशासन के
त : नितिन गडकरी

णामों को विकास और सुशासन के एजेंडे की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने हिन्दुत्व का मतलब भी सुशासन और विकास से ठबंधन सरकार के लिए नया एजेंडा तय करते म्मीद जताई कि बिहार जल्द ही देश के श्रेष्ठ ामिल होगा।

हा, यह जनता का सरकार के प्रति सकारात्मक तने भारी बहुमत से गठबंधन को जिताया है। हले राजद और फिर राजद–कांग्रेस की सरकार शासन के बाद पहली बार राज्य की जनता को रकार बदलकर भविष्य बदला जा सकता है। बसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने लोगों में किया। पहली बार राज्य में 45 हजार अपराधियों कूलों में टीचर और अस्पतालों में डाक्टर मौजूद ठीक ठाक हुई। बिहार जैसे राज्य में तरह के बदलाव की कोई कल्पना कर सकता था।

में रही। गौरतलब है कि 243 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए हुए राजग गठबंधन के तहत पिछली बार की तरह भाजपा ने 102 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसमें भाजपा को 91 सीटें मिली, जबकि पिछली विधानसभा में उसके पास मात्र 55 सीटें थीं। पार्टी को 36 अतिरिक्त सीटें मिली।

कांग्रेस की करारी हार

कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक के इतिहास में सबसे कम सीटें मिली। 2005 में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, इस बार उसकी झोली में मात्र 4 सीटें ही आ सकी। यहां तक कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर भी अपने क्षेत्र से धराशायी हो गये।

जहां-जहां चरण पड़े राहुल के...

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान का मोर्चा खुद संभाला था। यह चुनाव उनका इम्तिहान माना जा रहा था लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गये। उनका जादू नहीं चला। वे जहां–जहां गये, वहां–वहां कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। गौरतलब है कि राहुल ने बिहार में करीब 22 जगह चुनाव प्रचार किया। इनमें से सिर्फ 2 जगह ही कांग्रेस को जीत मिली।

राबड़ी देवी दोनों जगहों से हारी

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को करारा झटका लगा।

बिहार में ३२ महिलाएं भी एमएलए बनीं

महिलाओं को भी विधानसभा में 1962 के बाद सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। 32 महिलाएं एमएलए बनी हैं। खास बात यह है कि चुनाव में उतारे गए उम्मीदवारों में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 8.74 प्रतिशत ही थी. अगर पांच मुख्य पार्टियों सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपीए विपक्षी आरजेडीए एलजेपी और कांग्रेस के साथ वामपंथियों के उम्मीदवारों की फेहरिस्त पर नजर डाले तो कुल 90 महिलाओं को टिकट दिया गया. जेडीयू ने सबसे ज्यादा 24 और बीजेपी ने 11 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा. वहीं मौजूदा स्वरूप में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाली आरजेडी ने छह और एलजेपी ने सात महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया।

राजद ने 2005 में जहां 54 सीटें जीती थीं, वहीं इस बार वो 22 पर ही सिमट गई। पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी दोनों विधानसभा सीटों (राघोपुर और सोनपुर) से चुनाव हार गई। राघोपुर सीट से जनता दल (युनाइटेड) के उम्मीदवार ने राबडी देवी को हराया। जबकि सोनपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार विनय कुमार सिंह के हाथों राबडी देवी को हार का मुंह देखना पडा।

लोजपा की हालत खराब

सबसे खराब प्रदर्शन राजद की सहयोगी पार्टी लोकजन शक्ति पार्टी की रही। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 10 से 3 हो गई। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के दोनों भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान भी चुनाव हार गए।

विकास को वोट

लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कुशासन से बिहार का बुरा हाल हो गया था लेकिन गत पांच वर्षों में बिहार में राजग सरकार ने विकास की गंगा बहाई। राज्य के सभी क्षेत्र में अच्छी सड़कें बनवायी। सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारी। शिक्षा व्यवस्था को सुगठित किया। नए विद्यालय भवन निर्माण कराए। क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत करायी। शिक्षा प्रसार के लिए लड़कियों को मुफ्त में साईकिल बांटी। किसानों को सब्सिडी दी गई। उचित दाम पर खाद बीज उपलब्ध कराए गए। महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण पंचायत चुनावों में दिया। इसलिए इस बार के चुनाव की खासियत रही कि गुजरात चुनाव के बाद पहली बार बिहार में विकास चुनावी मुद्दा बना। ऐसे में राजग की जीत से यह सिद्ध हो गया कि आम लोग सुशासन और विकास चाहते हैं। बिहार चुनाव ने संदेश दिया कि जो विकास करेगा, वही जीतेगा। ■

एनडीए नेता बोले...

बिहार में भाजपा–जेडीयू की जीत भविष्य में देश की राजनीति की दिशा तय करेगी। 21वीं सदी की राजनीति जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर विकास और सुशासन की राजनीति होगी।

–नितिन गडकरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

अब पूरा देश बिहार का अनुसरण करेगा. विकास की भूख अब पूरे देश में जागेगी।

–सुषमा स्वराज, लोकसभा में विपक्ष की नेता

पहले डर था, इस बार उम्मीद थी. पहले निराशा थी. इस बार आशा थी. यह बिहार में परिवर्तन आया था. हमारे नेता नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने लोगों में विश्वास पैदा किया है. इस बार का मत सकारात्मक मत है और बिहार के भविष्य की उम्मीद का वोट है. परिणामों से साबित होता है कि अब क्षमतावान नेताओं की जीत होगी, परिवारवादियों की नहीं।

–अरुण जेटली, राज्यसभा में विपक्ष के नेता

बिहार में एनडीए की जीत विकास की जीत है। यह विकास की सोच रखने वालों की जीत है।

–नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री

एक बिहारी होने के नाते मुझे गर्व है कि बिहार ने जाति से ज्यादा विकास को तवज्जो देते हुए राजनीति का एक नया संस्करण लिखा है। यह बदलते बिहार का संकेत है। हालांकि, बिहार में अभी भी लालू का भय है, लेकिन नीतीश ने इस भय को कम कर सार्थक विकल्प पेश किया है।

–रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा

ये बिहार की जनता की जीत है। पिछले 5 साल में जिस तरह से हमारी सरकार ने विश्वास पैदा किया है। उसे लोगों ने सराहा है। अब बिहार को तरक्की की राह पर लेकर चलना है। अब एक तरक्की की कहानी लिखनी है। सरकार को और मेहनत की जरूरत है। जनता ने उन्हें दोबारा साथ दिया है अब सरकार अधूरी चीजों को पूरा करेगी।

–नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री

एनडीए सरकार ने पिछले पांच साल में बेहतरीन काम किया और जनता पर विश्वास बनाया। उसी का नतीजा है कि जनता ने हमें बहुमत दिलाया है। हमारी जीत बिहार की जनता की जीत है।

–सुशील कुमार मोदी, बिहार के उपमुख्यमंत्री

क्या श्रीमती (इंदिरा) गांधी ने अधिकृत कश्मीर को मुक्त कराने की योजना बनाई थी?

✍ ykyÑ".k vkMok.kh

गत् शुक्रवार 19 नवम्बर को प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह के साथ–साथ बड़ी संख्या में सांसद और पूर्व सांसद, संसद के सेंट्रल हॉल में श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र पर श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हुए थे।

पिछले कुछ सप्ताहों से एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूमता रहा है: 1971 में जब इंदिराजी ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों के लिए एक स्वतंत्र बंगलादेश बनाने हेतु शेख मुजीबुर्रहमान की सहायता करने का निर्णय लिया तो क्या साथ–साथ वे पश्चिमी पाकिस्तान में भी कोई ऑपरेशन करने का विचार कर रही थीं जो निम्नलिखित दो मुख्य उद्देश्यों को लेकर था–

1) पश्चिमी पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटना और
2) पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त कराना?

जब मैंने यह कहा कि कुछ सप्ताहों से यह प्रश्न मेरे दिमाग में घुमड़ रहा था, तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सितम्बर में, रूपा प्रकाशन ने मुझे एक पुस्तक भेजी। "बंगलादेश लिबरेशन वार–मिथ्स एण्ड फैक्ट्स" (Bangladesh Liberation War : Myths and Facts)। पुस्तक के लेखक कोई बी.जेड. खसरू हैं जिनके बारे में कवर–फ्लैप में वर्णित किया गया है : "एक पुरस्कार विजेता पत्रकार (जो) न्यूयार्क में एक वित्तीय प्रकाशन 'द कैपिटल एक्सप्रेस' के सम्पादक हैं।"

अभी तक मैंने ऐसा कभी किसी से कुछ सुना नहीं था। लेकिन यह पुस्तक इसके पर्याप्त आंकड़े देती है कि क्या श्रीमती गांधी ने वास्तव में इन उद्देश्यों को हासिल करने की योजना बनाई या नहीं, लेकिन उस समय के वाशिंगटन का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन

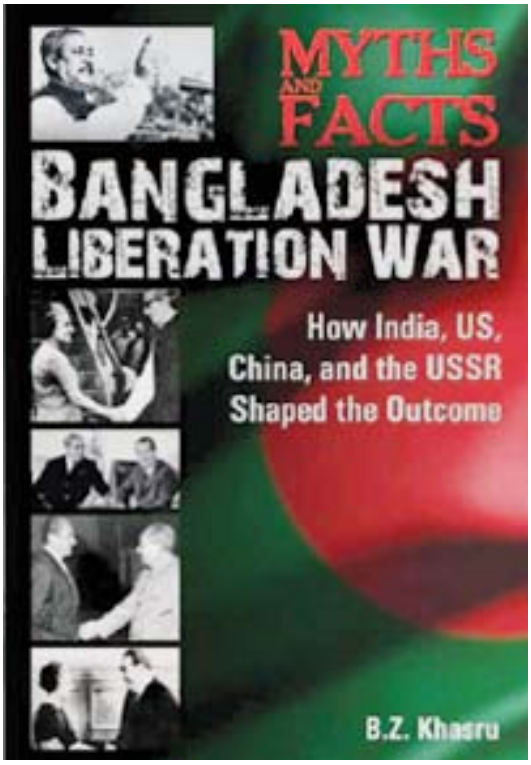

और राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर मानते थे कि श्रीमती गांधी इस दिशा में कार्रवाई करने का सोच रही हैं और भारत को इन उद्देश्यों को प्राप्ति में सोवियत रूस उनकी सहायता करेंगे।

उन दिनों में अमेरिकी–भारत सम्बन्ध काफी कटु थे और निक्सन को श्रीमती गांधी सख्त नापसंद थीं, अय्यूब और याहया अमेरिका की पसंद बन चुके थे। व्हाइट हाऊस में जनरल याहया खान के साथ राष्ट्रपति निक्सन की भेंट के बाद किसिंजर ने गंभीरता से पाकिस्तान के साथ संभावनाएं टटोली कि क्या वो चीन के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए अमेरिकी–चीन के रिश्तों को सुधार सकते हैं।

वास्तव में, पूर्वी बंगाल के सम्बन्ध में भारत–पाक संकट के समय अमेरिका ने न केवल बंगाल की खाड़ी में सातवां परमाणु बेड़ा रवाना किया था और चाहता था कि मास्को "भारत को पश्चिमी पाकिस्तान को तबाह करने से रोके, लेकिन यह भी प्रयास किया कि चीन भारत को पूर्वी पाकिस्तान में किसी भी सशस्त्र हस्तक्षेप के विरूद्ध धमकी दे।

क्या अमेरिका ने जो वास्तव में सोचा, क्या अमेरिकी धमकी और कार्रवाई से सचमुच में वह हासिल हुआ।

'बाल्कनाइज' वेस्ट पाकिस्तान : व्हाई गांधी बैक्ड ऑफ' शीर्षक वाले अध्याय में खसरू लिखते हैं–

जैसे भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में कूच करने लगीं तो संयुक्त राष्ट्र में युध्द रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में तेजी आने लगी, (श्रीमती) गांधी ने अपने को मुसीबतों और कठिनाइयों के बीच में पाया।

एक ओर, यदि वह पश्चिम में पाकिस्तानी सेना को कुचलने के लिए अपना अभियान जिसका वायदा उन्होंने महीनों पूर्व अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों

को किया था, तेज करतीं तो उन्हें वाशिंगटन और बीजिंग से सम्भावित युद्ध का सामना करना पड़ता तथा मास्को की नाराजगी झेलनी पड़ती जो चाहता था कि ढाका पर कब्जे के बाद युद्ध समाप्त कर दिया जाए। दूसरी तरफ, यदि वह पीछे हटतीं तो उनके सहयोगी उनके लिए परेशानी पैदा करते और भारत को अपने घोर शत्रु को स्थायी रूप से पंगु बनाने का अनोखा अवसर गंवाना पड़ता।

10 दिसम्बर को इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमण्डल को बताया कि यदि भारत बंगलादेश मुक्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो यह अमेरिका के साथ आगे की जटिलताओं को टाल सकता है और लद्दाख में चीनी हस्तक्षेप की वर्तमान संभावित संभावना को भी समाप्त कर सकता है। भारत के रक्षा मंत्री जगजीवन राम और अन्य अनेक सैन्य नेतृत्व ने तब तक युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार करने से मना किया जब तक भारत कश्मीर के निश्चित अनिर्दिष्ट क्षेत्रों को ले नहीं लेता और "पाकिस्तान के युद्ध तंत्र" को नष्ट नहीं कर देता। इंदिरा गांधी ने इन विरोधियों की सलाह को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि "फिलहाल भारत संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्पष्ट रुप से रद्द नहीं करेगा।" ढाका में अवामी लीग की सत्ता स्थापित हो जाने के बाद भारत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा।

लेखक की खोजों पर संदेह करने का कोई कारण मुझे नहीं दिखता। परन्तु इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात् मेरी इच्छा है कि कोई निष्पक्ष भारतीय इतिहासकार मुख्य रूप से अमेरिकी स्रोतों पर आधारित वर्णन को जैसा खसरु ने किया है, की तुलना में भारतीय सामग्री और भारत सरकार के दस्तावेजों के आधार पर शोध कर देश के सामने, हमारे पक्ष से घटनाओं के वर्णन को रखें।

कुल मिलाकर, यह पुस्तक उन सभी के लिए रोचक और पठनीय है जो हमारे इस उप–महाद्वीप के ताजा इतिहास में रुचि रखते हैं। ■

भ्रष्टाचार पर कांग्रेस कभी शर्मिन्दा नहीं हुई – अनुराग ठाकुर

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर द्वारा 19 नवम्बर को जारी प्रेस विज्ञप्ति

dkग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी द्वारा दिये गये इस बयान की कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा '2 जी स्पैक्ट्रम' घोटाले पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाना शर्मिंदगी का विषय नहीं है, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने आलोचना की। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं के लिए भ्रष्टाचार कभी भी शर्मिंदगी का विषय नहीं रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार कांग्रेस की कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाना पूरे देश के लिए शर्म का विषय है।

श्री ठाकुर ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने सब कुछ जानते समझते हुए 2 जी के नाम पर हो रहे खुलेआम भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास नहीं किया और न ही पूर्व संचार मंत्री ए. राजा के विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुमति दी जिसके कारण भारत सरकार को लाखों करोड़ रूपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। श्री ठाकुर ने कहा कि इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारियों के दौरान ही मीडिया, विपक्ष एवं स्वयं कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठतम नेताओं द्वारा खुलेआम हो रहे भ्रष्टाचार की बातें उठायी गयी थीं लेकिन कांग्रेस सरकार ने आयोजन समिति को खुलेआम भ्रष्टाचार करने का अवसर प्रदान किया। जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हुई और लाखों करोड़ रूपयों का नुकसान हुआ।

श्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों और '2 जी स्पैक्ट्रम' सौदों में हुए भ्रष्टाचार की बात किसी विपक्षी दल या आर.टी.आई. कार्यकर्ता द्वारा नहीं बल्कि कैग की रिपोर्ट में सामने आई है और 2 जी स्पैक्ट्रम, आदर्श सोसायटी व कॉमनवेल्थ खेलों में हुए घोटालों ने भ्रष्टाचार की सारी सीमायें लांघ दी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी को अब भी इसमें शर्मिंदगी जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ■

यूपीए - घोटालों द्वारा, घोटालों की, घोटालों के लिये सरकार

✍ vEck pj.k of'k"B

2 जी स्पैक्ट्रम घोटाला कोई एक दिन की करामात नहीं है। न यह सब कुछ रातों–रात घट गया कि किसी को भनक तक न लगी। यह उस दिन भी उजागर नहीं हुआ जिस दिन सीएजी की रिपोर्ट आने से पूर्व संचार मन्त्री ए राजा को त्यागपत्र देने पर मजबूर होना पड़ा।

इस घोटाले की परतें तो तब से ही खुलने लगीं थीं जब श्री ए राजा ने 2जी स्पैक्ट्रम की नीलामी शुरू की। पर प्रधान मन्त्री समेत कांग्रेस का कोई नेता यह मानने को तैयार ही न था कि इस में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट अखबारों में लीक हो जाने तक तो कांग्रेसी नेता और प्रधान मन्त्री श्री राजा का बचाव ही करते रहे । वह इस बात को कोई महत्व नहीं देते कि उनके इस आशीर्वाद से ही तो राजा सरकारी खज़ाने को ₹ 1.76 लाख करोड़ का चूना लगा गये। यह रकम छोटी नहीं पर इतनी बड़ी है जितनी कि राष्ट्र का सारे साल का सुरक्ष बजट। श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे ईमानदार प्रधान मन्त्री डा0 मनमोहन सिंह की नज़रों में तो इस में कुछ बुराई नहीं दिखाई देती। वह राजा को इतना ही निर्दोष व पाकदामन बताते हैं जितना कि वह स्वयं हैं।

कांग्रेस सर्वेसर्वा श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह देश की जनता को भ्रम की स्थिति में रखना चाहते हैं और वस्तुथिति से दूर रखना चाहते हैं। इसी कारण एक ओर तो वह राजा को निर्दाष व ईमानदार होने का सर्टिफिकेट देते हैं और दूसरी ओर उन्होंने जो कुछ किया उससे पल्ला झाड़ते फिरते हैं।

दोहरी नीति

यदि राजा ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया तो उनसे त्यागपत्र क्यों लिया गया?

यदि सरकार की बात ठीक है तो सीबीआई ने किस चीज़ की, किस अपराध की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है? शिकायत किसके विरूद्ध है और अपराध क्या है?

यदि कुछ गलत नहीं हुआ है तो टैलिफोन रैगुलेटरी अथारिटी ने एक सप्ताह के भीतर ही 69 लाइसैंस रद्द कर देने की शिफारिश क्यों कर दी है?

अब जब राजा का त्यागपत्र हो गया है तो यही कांग्रेस ऐसा आभास देना चाहती है कि मानो उसने तो देश के लिये कोई बहुत बड़ी शहादत ही दे मारी हो और अब तक उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ ईमानदारी और शुचिता का झण्डा ऊंचा रखने के लिये सारे का सारा न्यौछावर कर दिया हो।

यूपीए का ऊंचा मनोबल

कांग्रेस कई दशकों से बड़े–बड़े घोटालों को दबाने या उन पर कोई जांच या कार्यवाही सिर न चढ़ देने में काफी सफल रही है, चाहे वह मामला बोफर्स का हो, क्वात्रोची का हो, इराक में तेल घोटाले का हो। इस कारण उसका मनोबल काफी ऊंचा हो चुका है। यही उसने 2जी स्पैक्ट्रम मामले में भी करने की कोशिश की। पर इस बार लगता है कि कांग्रेस चूक गई और वह कुछ न कर पाई जो अब तक करने में वह सक्षम व सफल रही है।

सरकार को पता नहीं

कांग्रेस व सरकार की बातों में बहुत विरोधाभास है। एक ओर तो ये दोनों यह कहते फिरते है कि राजा ने कोई गलत काम नहीं किया और जो कुछ किया वह सरकार की नीति के अनुसार किया। दूसरी ओर ये दोनों ऐसा आभास देने का प्रयास कर रहे हैं मानो राजा के कार्यालय में उनकी नाक तले जो कुछ घट रहा हो उसकी सूचना ही नहीं थी। फिर यह कैसा संगठन या सरकार है जिसे अपनी ही सरकार में जो कुछ हो रहा हो उसका ही ज्ञान नहीं।

एक सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह सम्भव ही नहीं है कि प्रधान मन्त्री को सारे घोटाले की कोई भनक तक न लगे क्योंकि विभिन्न मन्त्रालयों में क्या ठीक–गलतश्र हो रहा है इसकी सूचना प्राप्त करने के लिये कई साधन हैं।

अनभिज्ञता सम्भव नहीं

इसका साफ निष्कर्ष निकलता है कि राजा जो कुछ भी ठीक या गलत कर रहे थे उसकी पूरी जानकारी कांग्रेस व सरकार दोनों को थी और सब कुछ उनकी स्वीकृति से हो रहा था।

फिर हमारे संविधान के अनुसार सरकार के हर कार्य के लिये समूचा मन्त्रिमण्डल संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता है। इस घोटाले में जो कुछ भी गलत या ठीक हुआ, उसके उत्तरदायित्व

से मनमोहन सरकार कैसे बच सकती है, विशेषकर जब स्वयं डा0 मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी एक स्वर से कह रहे हैं कि राजा ने कुछ गलत नहीं किया और वह निर्दोष हैं।

दूसरी ओर सरकार यह भी दावा कर रही है कि एक वर्ष से अधिक का समय हो गया जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। पर जांच में प्रगति न के बराबर है। अब जब मामला उच्चतम न्यायालय के पास पहुंचा तो न्यायालय को पूछना ही पड़ा कि तब राजा अभी भी मन्त्री क्यों बने बैठे हैं? (तब तक राजा ने त्यागपत्र नहीं दिया था)

25 नवम्बर को तो उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को और भी लताड़ा और पूछा कि अभी तक उसने राजा और तत्कालीन संचार सचिव श्री थामस (जिन्हें मनमोहन सरकार ने विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज के विरोध के बावजूद भी केन्द्रिय सतर्कता आयुक्त बना दिया है) से पूछताछ क्यों नहीं की जब कि सब को पता है कि इन लाईसैन्सों का आबन्टन किसी और ने नहीं इन दोनों ने किया था। इससे साफ हो जाता है सीबीआई मामले को सुलझाना नहीं टालमटोल कर उलझाना चाहती है।

अब जबकि सीएजी की रिपोर्ट आ गई है और उस में मन्त्रालय के कार्यकलाप पर गम्भीर आरोप और उसकी नीयत पर कई सवाल उठाये गये हैं तो इसके प्रशासकीय व राजनैतिक उत्तरदायित्व से कांग्रेस व सरकार कैसे अपना पल्ला झाड़ सकती है? सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संचार मन्त्रालय ने वित्तीय नियमों, प्रक्रिया व आदर्शों की धज्जियां उड़ाते हुये 2008 में 2001 की कीमतों के आधार पर 122 नये लाईसैन्स जारी कर दिये और प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्रालय के आदेशों की अवहेलना कर दी जिसने इस मामलें को मन्त्रियों के समूह को विचारार्थ प्रस्तुत करने की सलाह दी थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिन दस्तावेज़ों के आधार पर सीएजी ने राजा और उनके मन्त्रालय को दोषी पाया है वह तो सारे सरकार के पास हैं। फिर मनमोहन सिंह किस आधार पर कहते हैं कि राजा का कोई दोष नहीं है? दोष तो प्रधान मन्त्री जी की नज़र का लगता है जो इस सारे घोटाले में पाप देखना ही नहीं चाहती और उसे इस में केवल पुण्य ही दिखाई देता है।

दूसरी ओर उसे अपनी सरकार भी बचानी है चाहे देश जाये भाड़ में। वह राजा को हर सूरत में बचाना चाहती है क्योंकि सरकार की सांस तो डीएमके के समर्थन पर अटकी पड़ी है। वह उसे हर तरह से खुश रखना चाहती है ताकि उसकी सरकार बची रहे।

एक पहेली

असल में यह तो सारी एक पहेली ही लगती है। कहीं तो प्रधान मन्त्री कहते हैं कि उन्हें इस बारे कोई सूचना ही नहीं थी। कभी कहते हैं कि राजा ने जो कुछ किया वह सरकार की नीति के अनुरूप ही है। उधर संचार मन्त्रालय दावा करता है कि जो भी निर्णय लिये गये थे उनसे प्रधान मन्त्री कार्यालय को सूचित रखा गया था। जो भी हो इतना तो स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री व श्रीमती सांनिया गांधी दोनों ही इस घोटाले को रोकने में असफल रहे।

इस में कोई शक नहीं कि प्रधान मन्त्री के दिल में राजा के लिये बहुत स्नेहपूर्ण आशीर्वाद का भाव हैं।

संसद के केन्द्रिय कक्ष में जब प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री मुरासोली मारन को अपनी श्रद्धान्जली अर्पित करने पहुंचे और ए राजा के पास से गुज़रे तो राजा के अभिवादन पर डा0 मनमोहन सिंह ने बड़े स्नेह से उनकी पीठ थपथपा कर उन्हें आशीर्वाद दिया। वस्तुतः कांग्रेस तो अन्त तक राजा के त्यागपत्र की मांग का ज़ोरदार ढंग से विरोध करती रही। यह तो सीएजी की रिपोर्ट ने ही काम बिगाड़ा और राजा से त्यागपत्र मांगने पर मजबूर होना पड़ा।

मनमोहन का राजा पर स्नेह

अभी राजा के त्यागपत्र को कुछ ही दिन हुये थे तो सीएजी के एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये डा0 मनमोहन सिंह ने वहां उपस्थित अधिकारियों को उपदेश दिया कि वह गलत काम (wrongdoing) और सचमुच ईमानदार भूल (genuine error) में फर्क समझने का प्रयास करें। तो क्या हमारे प्रधान मन्त्री जनता को यह सन्देश देना चाहते हैं कि राजा ने जो गरीब जनता के खज़ाने को ₹ 1.76 करोड़ का चूना लगाया है और निजि कम्पनियों के न्यारे–व्यारे कर दिये हैं वह कोई अपराध नहीं मामूली सी सचमुच की एक छोटी सी ईमानदार भूल थी और उसी के लिये उन्होंने उस दिन राजा की पीठ भी थपथपाई थी?

लगता तो ऐसा है कि यूपीए समझ नहीं पा रही कि वह क्या करे और क्या न करे। इसी उठाहपोह की स्थिति के कारण ही प्रधान मन्त्री जनता पार्टी अध्यक्ष श्री सुब्रमन्यम स्वामी के उस पत्र पर भी सोये रहे जिसमें उन्होंने राजा पर मुकद्दमा चलाने के लिये स्वीकृति मांगी थी। पर जब स्वामी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खड़का दिया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा और कुछ टिप्पणियां कर दीं तो परेशान हो गये।

एक और इतिहास

भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी प्रधान मन्त्री को किसी न्यायालय ने अपना शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया हो।

पिछले 9 नवम्बर से संसद को दोनों सदनों में कोई काम नहीं हो सका है क्योंकि विपक्ष 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग पर अड़ा है जो इस सारे मामले की जांच करे। पर कांग्रेस व सरकार इस मांग का उतने ही ज़ोर से विरोध कर रहे हैं। वह कहते हैं कि इस के गठन का काई औचित्य व आवश्यकता नहीं है। सरकारी खज़ाने को जो 1.76 करोड़ की डस लगी। कांग्रेस केलिये उसका न कोई अर्थ है और न महत्व। यदि इस सारे मामले में कोई घपला नहीं है, कोई अपराध नहीं हुआ है और सरकार व राजा का दामन साफ है तो डरती क्यों है?

सिद्धान्त नहीं, गद्दी का खेल

कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति से इसलिये डरती है कि जांच के दौरान घपले की और परते न खुल जायें। यूपीए पहले ही इस वर्ष घोटालों के नये रिकार्ड कायम कर चुकी है। स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला अवश्य है जो कांग्रेस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने के रास्ते में हर सम्भव रोड़े अटकाना चाहती है। वह समझती है कि यदि राजा के गले में रस्सी अटकी तो उसे अपना गला बचाना भी मुश्किल हो जायेगा।

दूसरी ओर उसे अपनी सरकार भी बचानी है चाहे देश जाये भाड़ में। वह राजा को हर सूरत में बचाना चाहती है क्योंकि सरकार की सांस तो डीएमके के समर्थन पर अटकी पड़ी है। वह उसे हर तरह से खुश रखना चाहती है ताकि उसकी सरकार बची रहे। यदि सरकार चली गई तो घोटालों की राख के ढेर के नीचे सारी पार्टी दब कर रह जायेगी और वह जनता की नज़रों से भी ओझल हो जायेगी। फिर अगले वर्ष तमिलनाडू में विधान सभा चुनाव भी तो हैं। ■

किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का कार्य-विभाजन

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश धनकड़ ने अपनी टीम के कार्य विभाजन को अंतिम रूप दे दिया है। केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं वरिष्ठ सदस्यों को विभिन्न राज्यों के प्रभारी तथा विशेष कार्य सौंपे गए हैं। यह सूची इस प्रकार है:

jk"Vªh; mik/;{k

1. श्री ए. पाशा पटेल (मध्यप्रदेश)
2. श्री कृष्णा जगदेव (प. बंगाल)
3. श्री सुभाश मेहरिया (उत्तर प्रदेश)
4. श्री ऋषिपाल अंबावाता (उत्तराखण्ड)
5. श्री बिंदा प्रसाद सिंह
6. श्री सुरेश चंदेल, पूर्व सांसद
7. डॉ. रविन्द्र कुमार राय, झारखण्ड, अण्डमान और निकोबार

jk"Vªh; egkl fpo

8. श्री भुपेन्द्र सिंह चुडासामा गुजरात, दमन और द्वीव एवं दादर नागर हवेली
9. श्री ईश्वर चन्द्र होशमनी (आंध्रप्रदेश)
10. श्री नरेश सिरोही (दिल्ली) और केन्द्रीय कार्यालय

l fpo

11. श्री पी. सुगुंकर राव (कर्नाटक)
12. श्री शीलादित्या देव (पूर्वोतर)
13. श्री अनिल शर्मा (असम)
14. श्री मदन (केरल) और पाण्डेचेरी
15. श्री अशोक पटीदार
16. श्री सुखमिन्दर पाल सिंह ग्रेवाल (जम्मू और कश्मीर)
17. श्री अजित खत्री (हरियाणा)

dk"kk/;{k

18. श्री बलदेव भण्डारी ■

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

बिहार के चुनाव परिणाम विकास आस्था के परिणाम

✍ IR; iky

fcहार चुनाव के परिणाम चौंकाने और हतप्रभ करने वाले जरूर रहे, जिसने लालू प्रसादजी को सकते में डाल दिया और कांग्रेस ने तो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी मात्र चार सीटों पर सिमट कर स्वयं को ठिकाने पर लगती दीखने लगी है। जहां लालूजी बौखलाए रहे वहीं जनता और मीडिया ने एनडीए सरकार के पांच साल के सुशासन को जम कर सराहा।

स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस और उसके बाद पन्द्रह वर्षों के श्री लालू प्रसाद यादव की सरकारों ने बिहार को जिस दुर्गति की हालत में रखा, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में चल रहे जद(यू)–भाजपा गठबंधन का प्रयास रहा कि वह बिहार की जनता को सुबह की किरण दिखा सके और उसने भी विकास की बढ़ती गति को देखते हुए इस गठबंधन को पांच वर्ष और अवसर प्रदान करने का निश्चय कर लिया।

नीतीशजी विकास पुरुष के रूप में उभर कर सामने आए। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को विकास पुरुष कहलाने का सौभाग्य मिलता रहा है और वे आज इसी नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं।

बिहार की यह राजनीति, जिसमें जात–पांत और मजहबी हठधर्मिता को विकास यात्रा का आधार बनाया, वह कहां तक पूरे देश की राजनीति को बदल डालेगी, यह तो समय ही बतायेगा, परन्तु आने वाले भविष्य में इसी प्रकार की स्थितियां उत्तर प्रदेश में भी व्याप्त हैं, उनके लिए अवश्य ही अगले होने वाले चुनाव पथ प्रदर्शक का काम करेंगे, इस विषय में सपा, बसपा और कांग्रेस को अवश्य सावधान होने की आवश्यकता है, अन्यथा इन दलों को मुस्लिम और यादव, जिसे अंग्रेजी के 'माई' शब्द से प्रख्यात कर दिया गया है, और दलित एवं सवर्णों में विभाजन कर अपनी बदहाली देखनी पड़ेगी। भाजपा इसलिए आरम्भ से जात–पांत और छद्म–धर्म निरपेक्षता से उठकर देश को विकास के रास्ते पर चलने का संकल्प लेती रही है और इसी दिशा में चलती रही है। हमने सदैव छद्म–निरपेक्षता की राजनीति को छोड़कर 'सर्वधर्म समभाव' पर चलने के लिए कहा है। हमने 'न्याय सब के लिए, संतुष्टिकरण किसी का नहीं' राह अपना कर भले ही कुछ वोटों से हाथ धोया हो, परन्तु हम कभी सेक्युलरवाद से

स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस और उसके बाद पन्द्रह वर्षों के श्री लालू प्रसाद यादव की सरकारों ने बिहार को जिस दुर्गति की हालत में रखा, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में चल रहे जद(यू)–भाजपा गठबंधन का प्रयास रहा कि वह बिहार की जनता को सुबह की किरण दिखा सके और उसने भी विकास की बढ़ती गति को देखते हुए इस गठबंधन को पांच वर्ष और अवसर प्रदान करने का निश्चय कर लिया।

भटके नहीं हैं। यह बात और है कि मजहब की राजनीति करने वाली कांग्रेस, सपा, अथवा अन्य अनेक दल भाजपा को साम्प्रदायिक कहते रहे– जो किसी भी कसौटी पर सत्य नहीं उतरती है और बिहार के चुनाव इसका उदाहरण हैं जिसमें 'नीतीश–मोदी' गठबंधन को 54 अल्पसंख्यकबहुल सीटों में से 41 सीटों पर विजय दिलाई है। पूरे देश ने इस चमत्कार को देखा है और हमें आशा है कि पूरा देश इस आदर्श से अभिभूत रहेगा।

कांग्रेस और लालूजी के शासन में अराजकता और अव्यवस्था इस हालत तक जा पहुंची थी कि उनके शासनकाल में एक भी चुनाव 'मतपेटियों' के गबन से अछूता नहीं रहा।

हमें याद है कि टीवी पर नलिनीसिंह से अपनी 'आखों देखी' कार्यक्रम में मतपेटियों पर कब्जा करने और सामूहिक रूप से सत्ताधारी पार्टी को वोट दिलाने पर मुहर लगाते हुए दिखाया था बल्कि कहा तो यहां तक गया कि यह तो बिहार–संस्कृति का अंग है।

शायद यही कारण रहा कि लालू जी पन्द्रह वर्षों तक इस भ्रष्ट 'गड़बड़ी' का सहारा लेकर शासन के मठाधीश बने रहे। आज जब स्वयं लालू प्रसाद जी मानते हैं कि इस बार चुनाव में तो गड़बड़ी नहीं हुई फिर भी 'रहस्यात्मक चुनाव परिणाम क्यों आए, इसका हम पता लगाएंगे', ऐसा कह कर वह जनता की आंखों में धूल न झोंके, इसी में उनका कल्याण है।

राजद अध्यक्ष समझ लें कि इसका रहस्य कुछ नहीं है– यह विकास की जीत है, यह जनता की जीत है, यह स्वच्छ प्रशासन की जीत है, यह नीतीश–मोदी की युगल जोड़ी की स्वच्छ छवि की जीत है, यह उस लोकतंत्र की जीत है जिसमें वंशवाद भस्म हो गया है।

हां, इन चुनावों में वंशवाद को जिस प्रकार से लोगों ने धिक्कारा है, वह अपने आप में बिहार चुनावों का गौरव बनकर सामने आया है। लालूजी की राबड़ी देवी दोनों सीटों से हारीं, दलबदलकर कांग्रेस में गये श्री लालू के साले साहब हारे, श्री पासवान जी के भाई, दामाद आदि सभी किनारे लग गए।

काश! कांग्रेस भी वंशवाद की परम्परा छोड़कर सही लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचाने तो देश में सच्चे प्रजातंत्र के युग की शुरुआत हो।

इस बार के बिहार चुनाव में 'राहुल' फैक्टर नाम की बड़ी धूम मची हुई थी। कांग्रेसियों को बड़ा भरोसा था कि राहुलजी बिहार में चमत्कार कर दिखाएंगे और इसी भरोसे उन्होंने किसी दल के साथ गठबंधन भी नहीं किया और यह भी सच है कि राहुल गांधी ने बिहार में पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने, उनकी माताश्री श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने तो अपने चुनाव–दुष्प्रचार में खूब कहा कि बिहार में नीतीशजी ने केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए धन का उपयोग तक नहीं किया।

किन्तु 'जनता सब जानती है' और राहुल फैक्टर की चमक फीकी ही नहीं, बेकार साबित होकर रह गई और अन्ततः चुनाव परिणाम के बाद श्रीमती सोनिया गांधी को झेंपते हुए कहना पड़ा कि ''हमें बिहार में ज्यादह उम्मीद नहीं थी इसीलिए हमने जानबूझकर किसी दल के साथ गठबंधन नहीं किया।'' फिर भी, उपर्युक्त प्रकार का दुष्प्रचार कर क्यों जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई? यह 'लोकतंत्र–राजनीति' का अपमान नहीं तो क्या है?

विकास ही भाजपा–जद(यू) का मुद्दा था। यह मुद्दा ही नहीं था, बल्कि यह इस गठबंधन का संकल्प था जिसे नीतिशजी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में पूरी दृढ़ता से और पूरी इच्छाशक्ति से पूरा किया।

यह विकास कागजी घोड़ों की दौड़ नहीं थी, लोगों ने इसे 'सड़कों' पर देखा, शिक्षा, स्वास्थ्य में देखा, नक्सली हिंसा के बावजूद कानून व्यवस्था की बहाली में देखा– लोगों ने इस विकास को महसूस किया– यह चुनाव परिणाम ऐसे ही विकास आस्था का परिणाम हैं और हमें विश्वास है कि 'नीतीश–मोदी' अगले पांच वर्षों के कार्यकाल में अपनी गहरी लगन और संकल्प से इसे पूरा करते हुए बिहार को देश की प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिखाएंगे। ■

हां, इन चुनावों में वंशवाद को जिस प्रकार से लोगों ने धिक्कारा है, वह अपने आप में बिहार चुनावों का गौरव बनकर सामने आया है। लालूजी की राबड़ी देवी दोनों सीटों से हारीं, दलबदलकर कांग्रेस में गये श्री लालू के साले साहब हारे, श्री पासवान जी के भाई, दामाद आदि सभी किनारे लग गए। काश! कांग्रेस भी वंशवाद की परम्परा छोड़कर सही लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचाने तो देश में सच्चे प्रजातंत्र के युग की शुरुआत हो।

आइए, हम विश्वस्तरीय ढांचा तैयार करें और नगरों में जनजीवन रहने योग्य बनाएं : गडकरी

गत 19 नवम्बर को लखनऊ में आयोजित भाजपा महापौर तथा नगर–निगमों के पदाधिकारियों के द्वि दिवसीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने जोरदार अपील की कि आज हमारी आवश्यकता यह है कि हम सभी अपने शहरों के विकास के लिए दूरदृष्टि अपनाएं, सामूहिक राजनीतिक इच्छा से काम करें और भारत के शहरों को और बेहतर बना कर उन्हें रहने योग्य बनाएं। इसके लिए हमें अपने नगरों में विश्व–स्तर का बुनियादी ढांचा खड़ा करना होगा और जनजीवन को ऐसा बेहतर बनाना होगा जिसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए नवीनतम विकास के विचारों को प्रस्तुत करना होगा।

श्री गडकरी ने बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में स्वयं अपने अनुभव के आधार पर विस्तार से उल्लेख किया। सम्भवतः किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा आयोजित अपने किस्म का ऐसा सम्मेलन था जिसका स्पष्ट उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को बदलते नगरीय प्रशासकीय ढांचे के प्रति जागरूक करना था और उन्हें मुख्य नीतिगत भावी विषयों पर जानकारी देकर सशक्त बनाना था। इस सम्मेलन में 123 से अधिक महापौर, विपक्ष आदि ने हाऊस लीडर भाग ले रहे थे जिसका नाम दिया गया– नगरीय सूरज संकल्प सम्मेलन। इस अवसर पर अनेक भाजपा नेता मंच पर शामिल थे जिनमें कलराज मिश्र, सूर्यप्रताप शाही, विनय कटियार, अभिमन्यु, भूपेन्द्र यादव, पूर्व दिल्ली महापौर आरती मेहरा, राष्ट्रीय सचिव, सूरज पाण्डे आदि शामिल थे। लखनऊ के महापौर डा. दिनेश शर्मा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और पार्टी सचिव भूपेन्द्र यादव ने प्रारम्भिक भाषण दिया। श्री कलराज मिश्रा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री सूर्यप्रताप शाही ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अपने भाषण में उ.प्र. भाजपा अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही ने उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों की घोर उपेक्षा की तीव्र निंदा की जो संविधान के 74वें संशोधन की भावना का उल्लंघन है।

दोपहर बाद के सत्र में भाजपा सचिव सुश्री सरोज पाण्डे ने, जो दो बार दुर्ग की महापौर रह चुकी हैं, अपना प्रमुख भाषण दिया जिसमें उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक प्रशासकीय शक्तियां देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज नगरीय स्थानीय निकायों को और अधिक वित्तीय तथा कामकाज शक्तियां देने की जरूरत है। विवेक शेजवालकर, पूर्व ग्वालियर महापौर तथा भाजपा नगरीय नगरपालिका प्रकोष्ठ के संयोजक ने इस सत्र की अध्यक्षता की। बाद में भाजपा महासचिव–संगठन, श्री रामलाल ने प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें क्रमशः नागपुर और अहमदाबाद नगर–निगमों द्वारा 'सालिड वेस्ट मैनेजमेंट' और 'बीआरटीएस ट्रांसपोर्ट सिस्टम' के सर्वोकृष्ट पद्चिह्नों पर चलना चाहिए। सांयकाल में सामूहिक चर्चा रखी गई जिसमें सभी प्रतिनिधियों ने पार्टी द्वारा तैयार किए ''ड्राफ्ट चार्टर आफ कमिटमेंट' पर विस्तार से चर्चा की। ■

आज हमारी आवश्यकता यह है कि हम सभी अपने शहरों के विकास के लिए दूरदृष्टि अपनाएं, सामूहिक राजनीतिक इच्छा से काम करें और भारत के शहरों को और बेहतर बना कर उन्हें रहने योग्य बनाएं। इसके लिए हमें अपने नगरों में विश्व–स्तर का बुनियादी ढांचा खड़ा करना होगा और जनजीवन को ऐसा बेहतर बनाना होगा जिसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए नवीनतम विकास के विचारों को प्रस्तुत करना होगा।

कांग्रेस घोटालेबाजों की पार्टी है, इसे हटाने को भाजपा प्रतिबद्ध - नितिन गडकरी

नजफगढ़ में 14 नवम्बर को हुई भाजपा की विशाल जन आक्रोश रैली में गांव देहात, अनधिकृत कालोनियों आदि से जुटे 50 हजार से अधिक लोगों को सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने जोरदार शब्दों में कहा कि वर्तमान केन्द्र तथा दिल्ली सरकार घोटाला करने वालों की सरकार है। कांग्रेस की केन्द्र और राज्य सरकारें आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश में हुए सभी घोटालों की जानकारी प्रधानमंत्री को है। उनकी प्रचारित ईमानदार की छवि की कलई अब उतर चुकी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। 1.76 लाख करोड़ का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, 70 हजार करोड़ रूपये का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, अनाज सड़ाने का घोटाला, शशि थरूर–सुनन्दा आई.पी.एल. घोटाला आदि लाखों करोड़ों रूपये के घोटाले कांग्रेस सरकारें कर चुकी है। अब इस पार्टी और सरकार की पोल आम जनता में खुल चुकी है। इसका उदाहरण नजफगढ़ के मैदान में उमड़ा यह आक्रोशित जनसमुदाय है। लोग अब सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। यह कार्य भाजपा करेगी। उन्होंने घोषणा की कि ऐसी रैलियां भाजपा के शेष अन्य 13 जिलों में भी की जाएंगी।

कांग्रेस देश के लिए खतरा बन गई है। कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए भाजपा संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी। जन–जन, गांव–गांव जा कर इस जनविरोधी, पूर्ण भ्रष्ट तथा मंहगाई लाने वाली सरकार को सत्ता से हटना ही होगा। राजा तो जाएगा ही साथ में बैंड–बाजा बजाने वाली कांग्रेस सरकार भी जाएगी।

ज्ञात हो कि नजफगढ़ भाजपा जिले ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। रैली में भाग लेने के लिए लोगों में इतना उत्साह था कि वे नाचते–गाते, नारे लगाते हुए साईं मंदिर के सामने स्थित मैदान में एकत्रित हुए। मैदान 12.30 बजे तक पूरा भर गया था फिर भी जनता के आने का सिलसिला थमा नहीं। भाषण चलते रहे और हजारों की तादाद में नर–नारी रैली समाप्त होने के समय 3.30 बजे शाम तक मैदान में आते रहे। इस रैली में भाजपा नेताओं के भाषण सुनने के लिए लोग दीवानगी की हद तक पहुंच गए थे। हाथियों, नाचते घोड़ों, ढोल, नगाड़ों, ताशे, मजीरों, झांझों आदि के साथ नाचते हुए नर–नारी रैली स्थल पर पहुंच रहे थे। आज की रैली में 1977 के सत्ता परिवर्तन की याद ताजा कर दी। वास्तव में देश और दिल्ली के लोग कांग्रेस के लूटखोर शासन से आजिज आ चुके है और वे बदलाव चाहते है। श्री गडकरी का स्वागत करते हुए ग्रामवासियों ने उन्हें खेती का

प्रतीक चिन्ह हल भेंट किया।

श्री गडकरी ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए खतरा बन गई है। कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए भाजपा संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी। जन–जन, गांव–गांव जा कर इस जनविरोधी, पूर्ण भ्रष्ट तथा मंहगाई लाने वाली सरकार को सत्ता से हटना ही होगा। राजा तो जाएगा ही साथ में बैंड–बाजा बजाने वाली कांग्रेस सरकार भी जाएगी। उनका इशारा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मुखिया संचार मंत्री डी. राजा की ओर था।

श्री गडकरी ने सवाल किया कि राष्ट्रमंडल खेलों में हुए 70 हजार करोड़ रूपये के घोटाले की जांच के लिए बनाई गई शूंगलू कमेटी क्या प्रधानमंत्री, सम्पूर्ण मंत्रिमंडल, पीएमओ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आदि को पूछताछ के लिए बुला भी पाएगी? क्या इस कमेटी को इतने अधिकार दिए गए हैं? यदि नहीं तो जांच सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए ही की जा रही है।

उन्होंने रहस्योदघाटन किया कि खेल गांव बनाने वाली दुबई की कम्पनी के मालिक का बेटा राहुल गांधी का सचिव है। इसी कारण एम्मार एमजीएफ को यह ठेका मिला। इस ठेके में राहुल गांधी के सचिव ने 3100 करोड़ रूपये कमाए हैं। यूपीए सरकार के राज में सिर्फ भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों, दलालों, बिचोलियों, सट्टेबाजों का बोलबाला है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। गांव समाप्त हो रहे है। किसान दुखी है। हर साल 58 हजार करोड़ रूपये का अनाज सड़ रहा है और देश के 42 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद मुत अनाज नहीं बांटा जा रहा है। देश भूखा है और विदेशी बेंकों में भारत के बेइमानों का 70 लाख करोड़ रूपया जमा है। यदि इस रूपये को भारत लाकर विकास कार्य लगा दिया जाए तो देश का भाग्य बदल सकता है। कांग्रेसी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली को ऐसे लूट रही है जिस तरह नादिरशाह ने दिल्ली को लूटा था। रैली में आए लोगों का श्री गडकरी ने आवाहन किया कि वे इस निर्लज्ज, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहें।

राष्ट्रमंडल खेलों में हुए 70 हजार करोड़ रूपये के घोटाले की जांच के लिए बनाई गई शूंगलू कमेटी क्या प्रधानमंत्री, सम्पूर्ण मंत्रिमंडल, पीएमओ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आदि को पूछताछ के लिए बुला भी पाएगी? क्या इस कमेटी को इतने अधिकार दिए गए हैं? यदि नहीं तो जांच सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए ही की जा रही है।

रैली में भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने लोगों का आह्वान किया कि वे भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को बदल डाले। कांग्रेस को सिर्फ एक धक्का देने की जरूरत है। यह सरकार खुद मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन मिट्टी के मोल अधिग्रहीत करके कांग्रेसी नेता स्वयं तो मालामाल हो रहे हैं लेकिन किसानों को कंगाल कर रहे हैं। हरियाणा में एक करोड़ रूपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिल रहा है वहीं दिल्ली में 22 लाख रूपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा था जो भाजपा और किसानों के संघर्ष के आद बढ़ाकर 75 लाख रूपये कर दिया गया है लेकिन पूरा पैसा अब भी नहीं मिल रहा है। बढ़े सर्किल रेट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित भू माफिया के हाथों में खेल रही है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सर्किल रेट को लेकर चूहा–बिल्ली का खेल चल रहा है। दिल्ली और देश की जनता में कांग्रेस तथा उसकी सरकारों को लेकर भीषण आक्रोश है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। गांव उजड़ रहे है। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। शीला सरकार 12 साल के शासन के बावजूद गांव–देहात और किसान का दर्द नहीं समझ पाई है। अनधिकृत कालोनियों के निवासियों के साथ धोखे पर धोखा कर रही है दिल्ली सरकार। सीवर, पानी, पार्क, अस्पताल, स्कूल, सड़कों का आभाव दिल्ली के बाहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में है। अपराध बढ़ रहे है और मुख्यमंत्री जापान घूम रही है।

रैली को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जगदीश मुखी सहित अनेक लोगों ने सम्बोधित किया। रैली का सफल संचालन नजफगढ़ जिला अध्यक्ष सुमन कुमार शर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन भी उन्होंने ही किया। आज की रैली में विधायक धर्मदेव सोलंकी, प्रदुमन राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष आर.पी. सिंह, विजय जौली, सतीश उपाध्याय, विशाखा शैलानी, पवन शर्मा, प्रदेश महामंत्री रमेश विधूड़ी, आशीष सूद, प्रदेश मंत्री कमलजीत सहरावत, राजन तिवारी, डिप्टी मेयर राजेश गहलोत, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक श्रीकांत शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ संयोजक विवेक शर्मा सहित अनेक जिला अध्यक्ष, निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■

केंद्रीय मंत्री मध्यप्रदेश के नमक का कर्ज अदा करें : प्रभात झा

HKK रतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और सांसद प्रभात झा ने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश के सड़क और परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश से आते हैं। केंद्र में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। बावजूद इसके आज हमें राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत एवं दुर्दशा के लिए सडक पर उतरना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश से सड़क परिवहन मंत्री होने के बावजूद 65 हजार किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों में से लगभग 4 हजार किलोमीटर मध्यप्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्गों में हिस्सा है। पिछले कई वर्षों में मंत्री जी द्वारा कोई प्रयास नहीं हुआ, जिससे की मध्यप्रदेश की सडकों को राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल किया जाए। अपितु विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग अपने जीवन का संघर्ष करते दिखाई दे रहा है। गत एक वर्ष से अधिक समय होने पर भी एक रुपये की राशि भी मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाब के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं की गई, जो कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि केंद्र की सरकार अपने पक्षपातपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण रवैये से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस की इस वैमनस्यतापूर्ण, पक्षपातपूर्ण एवं भेदभाव से ग्रसित केन्द्र सरकार की इन नीतियों का खमियाजा मध्यप्रदेश की 7 करोड़ जनता भुगत रही है।

श्री प्रभात झा ने कहा कि केन्द्र की कांग्रेस सरकार को मध्यप्रदेश की जनता ने 4 मंत्री चुनकर दिए हैं, जो कि मध्यप्रदेश की जनता से विकास का वादा करते हैं, जो कि मध्यप्रदेश में निवास करते हैं, जो कि मध्यप्रदेश के नागरिक हैं एवं जिनका पूर्ण राजनीतिक जीवन मध्यप्रदेश के मतदाताओं के

विश्वास पर चलता है, या कहें कि यह सभी मंत्री मध्यप्रदेश का नमक खाते हैं, परन्तु मध्यप्रदेश के नमक के कर्ज को अपने राजनीतिक विलासिता में भूल गए हैं। यह समय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राष्ट्रीय राजमार्गों के विषयों में मध्यप्रदेश का नमक याद करते हुए अपने फर्ज का निर्वहन करें। हमारा यह प्रदर्शन का कार्यक्रम चेतावनी एवं प्रतीक स्वरूप है। यदि इस कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्री अपने कुंभकरणीय नींद से नहीं जागे तो जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी जनता में इस आंदोलन को और आक्रामक रूप से लेकर जाएगी, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश की 7 करोड़ जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसी भी कीमत पर करेगी।

श्री प्रभात झा 20 नवम्बर को भोपाल के 11 मिल तिराहे से राष्ट्रीय राजमार्ग बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 11 मिल तिराहे से पैदल मार्च किया गया जिसमें प्रदेश मंत्री रामेश्वर शर्मा, सरिता देशपांडे, प्रदेश प्रवक्ता विजेश लूनावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ.हितेश वाजपेयी, प्रदेश कार्यालय मंत्री आलोक संजर, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष साधना सिंह, वरिष्ठ नेत्री सीमा सिंह, जिलाध्यक्ष आलोक शर्मा, जिलाध्यक्ष ग्रामीण भक्तपाल सिंह, विधायक विश्वास सारंग, रुद्रनारायण सिंह, सुरेन्द्रनाथ सिंह, ओम यादव, प्रकाश मीरचंदानी, सत्यार्श अग्रवाल, सुनील पांडे, लिली अग्रवाल, अशोक सैनी, महेश शर्मा, आशा जैन, मालती राय, नवल प्रजपति, महेश मकवाना, अजय शर्मा, राकेश शर्मा सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए पैदल मार्च किया। ■

हम गढ़ रहे 2020 का छत्तीसगढ़ : रमन सिंह

महज दस साल की उम्र में छत्तीसगढ़ ने देश में भले ही अपनी अलग पहचान बना ली हो लेकिन उसके पहिए अभी थमे नहीं हैं। छत्तीसगढ़ बनने के 10 साल पूरे होने पर 'दैनिक भास्कर' से विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि अभी मंजिल बहुत दूर है। हम 2020 का विकसित छत्तीसगढ़ गढ़ने में लगे हैं। हमारा लक्ष्य विकास के मामले में गुजरात और समाज सेवा में केरल को पीछे छोड़ना है। बातचीत के अंश..

छत्तीसगढ़ के १० वर्ष हो गए, अब आगे क्या लक्ष्य है?

देश में गुजरात और केरल पुराने व विकसित राज्य हैं। गुजरात विकास के मामले में आगे बढ़ा है और सामाजिक क्षेत्र में केरल में अच्छा काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ दोनों से आगे हो। लक्ष्य काफी बड़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ संसाधन और संभावनाओं वाला प्रदेश है।

कोई मंजिल तय की होगी?

हां, हम 2020 का छत्तीसगढ़ तैयार करने में लगे हैं। सरकार की सोच और कार्ययोजना में यह साफ दिख रहा है। दिशा तय कर काम किया जा रहा है।

किस आधार पर आगे बढ़ेंगे?

विकास के शिखर को छूना कोरी कल्पना नहीं है। पिछले सालों में छत्तीसगढ़ ने अपना आधार तैयार कर लिया है। कृषि, बिजली, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में जिन कामों ने राज्य को पहचान दिलाई वही काम आगे चलकर राज्य को शिखर पर बैठाएंगे।

शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के संस्थान अब पहले से बेहतर काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में ठोस नीतियों के परिणाम दिखने लगा है। औद्योगिक विकास की तस्वीर आम आदमी के सामने है। इसमें राज्य की ताकत के रूप में लोहा, कोयला और अन्य खनिज भंडारों का महत्वपूर्ण रोल होगा।

राज्य की प्रमुख ताकत क्या हैं?

खनिज और खेती इस राज्य की दो सबसे बड़ी ताकत हैं। इनकी बदौलत राज्य हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। फिर बिजली तो है ही। देश के कई राज्यों की बिजली जरूरतों को पूरा करने की क्षमता छत्तीसगढ़ में है। 49 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से देश का पावर हब बनेगा।

नक्सल मोर्चे पर क्या रणनीति में बदलाव किया जाएगा?

सरकार अभी जिस रणनीति के साथ काम कर रही है, उसमें कुछ खास बदलाव की जरूरत नहीं है। दीर्घकाल में इसके अच्छे परिणाम आएंगे।

नक्सलियों से कुछ बोलना चाहेंगे?

नक्सली गतिविधियों में संलिप्त लोगों को यह सोचना होगा कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है? सरगुजा से लेकर बस्तर तक आम लोग विकास चाहते हैं। कोई भी इस तरह की हिंसा को पसंद नहीं करता।

नक्सलियों से वार्ता के पक्ष में हैं?

नक्सलियों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। अगर उनको बातचीत में कोई तकलीफ नहीं है तो राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं भी सहर्ष तैयार हूं। देशव्यापी बातचीत प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं।

अगर राज्य में बातचीत का माहौल बनता है तो इसमें खुशी होगी। सरकार को राज्य में शांति चाहिए और शांति की स्थापना के लिए हर उस उपाय को सरकार अमल में लाने के लिए तैयार है। ■